प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ... सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

एक उद्देश्य के लिए काम करें, तालियों के लिए नहीं। अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए जिएं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं।

गौर गोपाल दास

वर्ष-07, अंक-41 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 10 जुलाई 2025 | पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

आटे में नमक नहीं नमक में आटा...

माही की गूंज झाबुआ, संजय भटेवरा।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली भाजपा सरकार में नित नए भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आ रहे हैं। जिसके बाद आम चर्चा का विषय है कि क्या भाजपा का यही जीरो टॉलरेंस है....! वर्तमान समय पर भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है और हर कोई यह कहता नजर आ रहा है कि, बिना लिए-दिए ऑफिसो में कुछ काम ही नहीं होता है और कई लोग तो यह भी कहते हैं आटे में नमक जितना भ्रष्टाचार तो ठीक है लेकिन पिछले कुछ मामलों में तो आटे में नमक नहीं नमक में आटा मिलता नजर आ रहा है। ताजा मामला शहडोल जिले के ब्योहारी विकासखंड स्थित शासकीय हाई स्कूल सकंदी और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपानिया का सामने आया है। जहां इन दोनों स्कूलों में 24 लीटर ऑयल पेंट लगाने के लिए 443 मजदूर व 215 मिस्त्रियों को लगाया गया व 3.38 लाख के बिलों का भुगतान किया गया।

जिसमें संकदी में चार लीटर ऑयल पेंट की खरीद की गई थी जिसकी कीमत 196 रुपये प्रति लीटर के मान से 784 रुपये बताई गई यह तो ठीक है लेकिन इस पेंट को दीवार पर पोतने के लिए 168 मजदूरो और 65 मिस्त्रियों से काम करना बताया गया और इसके बदले उन्हें एक लाख छ हज़ार नो सौ चोरासी रुपये का भुगतान किया जाना बतलाया गया। इसी तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निपानिया में 20 लीटर पेंट के लिए 275 मजदूर और 150 मिस्त्रियों को कुल मजदूरी 231650 रुपये भुगतान किया जाना दर्शाया गया। यानी कुल 24 लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए इतनी भारी भरकम राशि खर्च की गई। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में सरकार की नाक बचाने के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई।

जिसके बाद आम जनता का कहना है कि, यह कार्यवाही महज प्रशासन का ढकोसला है क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार महज प्रिंसिपल नहीं कर सकता है, इसमें निश्चित रूप से बड़े अधिकारियों का हिस्सा शामिल रहा होगा लेकिन कार्यवाही केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही की जाती है।

यही नहीं यह केवल एक विभाग के दो स्कूलों का मामला है जिसके सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। ऐसे कई विभागों के कई कार्यालयो और स्कूलों में भी हो सकते हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए क्या प्रशासन उनकी जांच करेगा...?

पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश सहित केंद्र में भाजपा की सरकार है ऐसे में भाजपा का जीरो टॉलरेंस नीति का दावा खोखला ही साबित हो रहा है। क्योंकि बड़ी संख्या में न केवल भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे है वरन कई शासकीय सेवक भी रिश्वत लेते लोकायुक्त की कार्यवाही में पकड़ आ रहे हैं। जिसके बाद जनचर्चा बनी हुई है कि, मोहनराज में अफसर शाही और ज्यादा बे लगाम हो चुकी है और जनप्रतिनिधियों तक की नहीं सुनी जा रही है। जिसका ताजा उदाहरण ग्राम खवासा का है जहां भाजपा समर्थित जनपद उपाध्यक्ष को अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ नर्मदा की पाइपलाइन के आउटलेट के लिए जन आंदोलन करना पड़ा। सांसद और मंत्री के संज्ञान में भी मामला आया उसके बावजूद नर्मदा पाइपलाइन का आउटलेट खवासा तालाब के लिए नहीं दिया गया। जिसके बाद जन प्रतिनिधि अपने आप को असहाय महसूस कर रहे। क्योंकि वे आम जनता से चुनाव के दौरान किए गए वादे पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता की जायज मांग पूरी नहीं हो रही है और नौकरशाही दोनों हाथों से शासन को चूना लगाने में जुटे हैं। ये दो स्कूल तो मात्र उदाहरण है अगर पूरे प्रदेश में हर काम की सही व निष्पक्ष ऑडिट की जाए तो कई इससे भी बड़े मामले सामने आ सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि करें कौन...?

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की न्यायिक हिरासत बढ़ी

नई दिल्ली, एजेंसी।

26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत ने यह आदेश दिया। साथ ही एनआईए ने राणा के खिलाफ पूरक आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया है। अदालत अब 13 अगस्त को इस पूरक आरोप पत्र पर सुनवाई करेगी।

यह राणा के खिलाफ जांच एजेंसी की दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले 2011 में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें तहव्वुर राणा को डेविड हेडली और अन्य आतंकवादियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रचने वाला बताया गया था। एनआईए की पूछताछ में राणा ने कबूला कि वह 26/11 हमले के समय मुंबई में मौजूद था और पाकिस्तान की सेना का एजेंट है। उसने माना कि उसने हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मदद की थी।

तहव्वुर राणा को अक्टूबर 2009 में अमेरिका के शिकागो में वहां की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने गिरफ़्तार किया था। 10 अप्रैल 2025 को उसे विशेष विमान के जरिए अमेरिका से भारत लाया गया था। इससे पहले सोमवार को खुलासा हुआ था कि 26/11 के दौरान राणा मुंबई में मौजूद था। एनआईए सूत्रों के अनुसार, राणा ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि उसने पाकिस्तान में डेविड हेडली के साथ लश्कर-ए-तैयबा के कई प्रशिक्षण शिविरों में भाग लिया था। राणा ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा असल में एक जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है।

पूछताछ में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा भी शामिल थी। अब अपराध शाखा राणा को गिरफ़्तार कर अपनी हिरासत में लेने की तैयारी कर रही है।

हादसाः माही नदी में गिरे चार वाहन, 4 की मौत, कई घायल

वडोदरा।

गुजरात के वडोदरा और आणंद जिलों को जोड़ने वाला पादरा-गंभीरा पुल बुधवार सुबह ढह गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 8 बजे माही नदी पर बने इस पुल के गिरते ही उस पर से गुजर रहे दो ट्रक, एक बोलेरो और एक जीप नदी में गिर गई।

अब तक चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में चल रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोग, प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। गोताखोरों की मदद से पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।

पुल के गिरने के कारण माही नदी में गिरे वाहनों को निकालने का अभियान जारी है। घटना के बाद वायरल हुए चित्रों में एक बड़ा टैंकर पुल की टूटी रेलिंग पर फंसा दिखा।

यह पुल मध्य गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी थी और कई बार प्रशासन को इसकी मरम्मत के लिए कहा गया था, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया गया। हादसे के बाद प्रशासन ने जांच के लिए तकनीकी समिति का गठन कर दिया है। सड़क और भवन विभाग के सचिव पी.आर. पटेलिया ने बताया कि पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और विस्तृत जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम भेज दी गई है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस हादसे ने गुजरात में पुलों के रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और अन्य संभावित पीड़ितों की तलाश की जा रही है।

आतंक की साजिश नाकामः पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों का जखीरा पकड़ा

चंडीगढ़।

पंजाब में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में छिपा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में हिंसा फैलाने की योजना बना रहा था। इसी साजिश के तहत पाकिस्तान से हथियारों की एक बड़ी खेप पंजाब भेजी गई थी।

पंजाब पुलिस की आतंकवाद विरोधी इकाई ने भारत-पाक सीमा के पास अभियान चलाकर इस खतरनाक खेप को बरामद कर लिया। इसमें एके-47 राइफलें, हथगोले और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये हथियार पंजाब सहित देश के अन्य हिस्सों में बड़े हमले करने के मकसद से भेजे गए थे।

सूत्रों के अनुसार, आईएसआई की मदद से रिंदा स्थानीय अपराधियों और अलगाववादियों को साथ जोड़कर पंजाब में आतंकी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान सीमा के पास एक गुप्त ठिकाने से ये हथियार बरामद किए गए। पुलिस अब इस हथियार तस्करी के नेटवर्क में जुड़े अन्य लोगों और आतंकी संगठनों की तलाश कर रही है। हरविंदर सिंह रिंदा लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। वह पहले भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है।

लड़ाकू विमान गिरा, दो पायलटों की मौत

जयपुर।

राजस्थान के चुरू जिले में बुधवार को वायुसेना का एक लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद खेतों में बिखरे मलबे से दो पायलटों के शव बरामद किए गए। यह विमान भारतीय वायुसेना का दो सीटों वाला 'जगुआर' था, जो सूरतगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान भरकर रवाना हुआ था।

दुर्घटना दोपहर करीब 1 बजकर 25 मिनट पर रतनगढ़ क्षेत्र के भनोदा गांव के खेतों में हुई। ग्रामीणों ने तेज धमाके की आवाज सुनकर आसमान में धुएं का गुबार उठते देखा। मौके पर पहुंचे लोगों ने खेतों में विमान का बिखरा हुआ मलबा और उसमें लगी आग देखी। ग्रामीणों को वहां दो पायलटों के क्षत-विक्षत शव भी दिखाई दिए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और इलाके को घेर लिया गया।

हादसे के बाद गांव में दहशत फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के पास जमा हो गए। पुलिस ने लोगों को दूर हटाकर मलबे से शव बाहर निकाले।

बताया जा रहा है कि पिछले चार महीनों में वायुसेना के तीन 'जगुआर' विमान हादसों का शिकार हो चुके हैं। इससे पहले 7 मार्च 2025 को हरियाणा के पंचकूला में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान एक 'जगुआर' गिरा था, जिसमें पायलट सुरक्षित बच गया था। वहीं 2 अप्रैल 2025 को गुजरात के जामनगर में अभ्यास के दौरान ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें एक पायलट की जान चली गई थी। जगुआर विमान ब्रिटेन और फ्रांस की संयुक्त परियोजना है, जिसे गहराई तक हमला करने के लिए तैयार किया गया था। भारत ने इसे 1979 में वायुसेना में शामिल किया था। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। भारतीय वायुसेना में इसे 'शमशेर' नाम दिया गया है। करगिल युद्ध सहित कई बड़े अभियानों में इसका उपयोग किया गया है। भारत में इसका निर्माण हिंदुस्तान विमान निर्माण कारखाना (एचएएल) ने भी किया है।

जस्टिस वर्मा का छिनेगा पद ! सरकार ने दी महाभियोग को मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी।

घर में नकदी मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा की कुर्सी छिनने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। सरकार ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे 21 जुलाई से शुरू होने वाले वर्षा सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसे पहले राज्यसभा में लाया जाए या लोकसभा से पारित कराया जाए।

विपक्ष के सांसद भी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार हैं। केवल कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि जस्टिस शेखर यादव पर भी महाभियोग लाया जाए, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में सांप्रदायिकता फैलाने वाला बयान दिया था।

गौरतलब है कि महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश करने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है।

हालांकि इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण चरण है। संसद में प्रस्ताव पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा एक जांच समिति गठित की जाती है। इस समिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रख्यात कानून विशेषज्ञ को शामिल किया जाता है। यदि समिति अपनी रिपोर्ट में संबंधित न्यायाधीश के आचरण को दोषपूर्ण पाती है, तो फिर संसद में प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जो संबंधित न्यायाधीश को पद से हटाने का अंतिम निर्णय लेते हैं। यदि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है, तो वह महाभियोग प्रक्रिया के तहत हटाए जाने वाले देश के पहले न्यायाधीश बन जाएंगे।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में एक समिति बनाई थी, जिसने जस्टिस वर्मा की भूमिका को गलत ठहराया था। इस मामले में 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। पूरी रिपोर्ट पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को महाभियोग की सिफारिश के साथ भेजी थी।

गांधी का आरोप - बिहार में भी दोहराई जाएगी महाराष्ट्र जैसी चुनावी साजिश

पटना, एजेंसी।

बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन अभियान के विरोध में बुधवार को महागठबंधन द्वारा आयोजित बिहार बंद ने प्रदेश भर में असर दिखाया। इस दौरान कई जिलों में ट्रेनें रोकी गईं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगाया गया।

प्रदर्शन में शामिल होने कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पटना पहुंचे। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। इनकम टैक्स चौराहे से सभी नेता एक वाहन पर सवार होकर चुनाव आयोग कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन सचिवालय थाना के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। नेताओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। चुनाव आयोग कार्यालय वहां से मात्र 150 मीटर की दूरी पर था। नेताओं ने वहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और लौट गए। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष के जनमत को कुचलकर चुनाव लूटा गया था और अब वही साजिश बिहार में रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है और गरीबों के वोट छीनने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी ने कहा, ÷हमारे प्रतिनिधि चुनाव आयोग से मिले, लेकिन आयोग के अधिकारी भाजपा और संघ के नेताओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि वे संविधान के तहत काम कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। कानून आपको बाद में कटघरे में खड़ा करेगा।÷

बिहार बंद के दौरान समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहारी, वैशाली, पटना और औरंगाबाद सहित कई जिलों में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों जाम रहे। दरभंगा, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, मुंगेर और अररिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रोका गया। महागठबंधन के इस बंद में राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल, विकासशील इंसान पार्टी, जन अधिकार पार्टी समेत छह से अधिक दल शामिल रहे।बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

भोपाल से तो कार्रवाई के सख्त निर्देश लेकिन यहां मिल रही पनाह

प्रशासन की उदासीनता झोलाछाप डॉक्टरों के लिए बनी वरदान

माही की गूंज, खवासा (सुनील सोलंकी)

ग्रामीण अंचलों में एमबीबीएस की तर्ज पर अपने क्लीनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाया है। मामला ठन्डे बस्ते में चले जाने के बाद झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस बघेल ने आदेश क्रमांक 2709/ 21 अप्रेल 2025 जारी करके फिर अवैध चिकित्सकों के ऊपर कारवाई करने के लिए बीएमओ को निर्देशित कर दिया है। अब देखते हैं स्वास्थ्य विभाग में बीएमओ है जो महीना बंदी लेने वाले कब तक कार्रवाई करते हैं! क्योंकि आदेश तो पूर्व में भी मोहन सरकार ने दिए थे ही अवैध चिकित्सकों पर कार्रवाई के लेकिन उन आदेशों को भी घोल के पी गए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर आदेश जारी किया है। और इन आदेश मे अवैध अपंजीकृत चिकित्सक के साथ जहां लैब टेक्नीशियन अगर मरीज की जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। लेकिन क्या कार्रवाई होती है देखना दिलचस्प होगा।

वही सूत्रों की माने तो एक-दो बार कार्रवाई करने के लिए अमला पहुंचा भी था। लेकिन मामले में किसी ने विभीषण की भूमिका अदा कर दी इसकी वजह से अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही झोलाछाप डॉक्टर अपनी दुकान बंद करके रफू चक्कर हो गए। उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। जिले सहित ग्रामीण अंचलों में इनका मायाजाल बड़े लंबे व जोड़ जुगाड़ के साथ जमा हुआ है। यह ग्रामीण अंचलों में ग्रामीणों को हाई डोज देने के साथ ही बिना जांच पड़ताल किए बोतल व इंजेक्शन तक लगाते हैं। अभी भी इनके धडल्ले से क्लीनिक चल रहे हैं। जबकि भोपाल से आदेश आने के बाद प्रशासन को इन पर शिकंजा कसना था लेकिन शिकंजा कसने के बजाय विभागीय अधिकारी मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। थांदला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीन खवासा, सूजापुरा, भामल आदि जगह झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि पिछ्ले दिनों टीएल बैठक में कलेक्टर ने इनके ऊपर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

आखिर क्या वजह की इन पर आदेश होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना? जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। लेकिन झाबुआ जिले में मामला ठन्डे बस्ते में चला गया।

जैसे ही भोपाल से कार्रवाई करने के आदेश जारी हुए इन झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ था लेकिन अब निडर होकर यह अपने अवैध क्लिनिक चला रहे हैं। तो मेडिकल की आड़ में धड़ल्ले से ग्रामीणों का इलाज भी कर रहे हैं।

भामल मे मेडिकल की आड़ मे अवैध इलाज कर रहे झोलाछाप

ना स्वास्थ्य विभाग का अमला ना ही ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी भामल सहित खवासा में निरीक्षण करने नहीं पहुंची...! खवासा के समीप ग्राम भामल में दो मेडिकल संचालित हो रहे हैं, लेकिन इन मेडिकल संचालकों ने इन दिनों धूम मचा रखी है। मेडिकल की आड़ में यह ग्रामीणों का इलाज भी कर रहे हैं। जबकि मेडिकल संचालित करने वाले को सिर्फ डा. की पर्ची के आधार पर मेडिकल पर दवाई देना रहता है। लेकिन यह धड़ल्ले से मिनी नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बताते हैं। पिछ्ले दिनों ड्रग इंस्पेक्टर ने ग्रामीण अंचलों में संचालित हो रहे। मेडिकल का दौरा किया था लेकिन खवासा व भामल में मेडिकलों का दौरा ही नहीं किया। भामल, खवासा में मेडिकल की आड़ में इलाज ग्रामीणों का किया जा रहा है। खवासा मे कुमार मोहल्ले मे अजित राय व भामल मे दिपक चौहान व गौतम राय मेडिकल संचालित करने के साथ उसी जगह मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है, जबकी यह नियमों के खिलाफ है। वही झोलाछाप की दिन दुगनी और रात चुगनी की तर्ज पर मरीजों को लूटा जा रहा है।

मेडिकल की आड़ में इस तरह से मरीजों का इलाज करते हुए

कलेक्टर के आदेश को भी नजर अंदाज कर गए स्वास्थ्य अधिकारी

जिले में कलेक्टर नेहा मीना ने इन पर शिकंजा कसने के लिए टीम का गठन किया है। लेकिन टीम अब तक सक्रिय नहीं हो पाई है। जिससे इनके हौसले अभी भी बुलंद है। कलेक्टर ने सख्त आदेश दिया है और अपंजीकृत चिकित्सक पर शिकंजा कसने के लिए ब्लॉक के एसडीएम व बीएमओ एवं थाना प्रभारी को संयुक्त दल के साथ सदस्य नियुक्त किया हैं। जानकारों का मानना है कि जिले सहित ग्रामीण अंचलों में कई जगह अपंजीकृत चिकित्सक अवैध तरीके से अपने क्लीनिक का संचालन कर रहे इनके क्लीनिक पर हर दिन काफी मरीज पहुंचते हैं। यह अवैध चिकित्सक दवाई रखने के साथ बोतल व इंजेक्शन का भरपूर उपयोग करते हैं। वही ज्यादा स्थिति गंभीर होने पर ही मरीज को अन्य अस्पताल ले जाने का खर्चा भी देते है।

खवासा में दो निजी लैब शुरू हुई

अवैध चिकित्सकों के साथ-साथ खवासा में दो निजी लैब भी खुल गई है, जिनका संचालन किराए पर रखे हुए टेक्नीशियन ही संचालन कर रहे हैं। जिनको 8 से 10 हजार रुपये महीना दिया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि, टेक्नीशियन लैब नहीं चला सकते हैं, मोके पर एमडी पैथोलॉजिस्टिक होना जरूरी है।

उनकी अनुमति के बगैर कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती लेकिन यहां सिर्फ कागजों में सही दर्शा कर निजी लैब धड़ल्ले से चला रहे है, जबकि खवासा में कोई भी एमड़ी पैथोलॉजिस्टिक बाहर से भी अभी तक कोई भी लैब में निरीक्षण करने नहीं आया। सिर्फ 8 से 10 हजार महीने के हिसाब से लड़कों को रखकर लैब में रिपोर्ट मरीजों की तैयार की जा रही है जो एक जांच का विषय है।

यह अपंजीकृत चिकित्सक कर रहे हैं खवासा वह भांमल में इलाज

खवासा कुलदीप हाड़ा, शुभम प्रजापत, प्रवीण पाटीदार, हैतल हाड़ा, अभिजीत मंडल, अजित राय, दिपक वसुनिया।

भामल मे दिपक चौहान, गौतम राय, मोहितेश मण्डल, आदि धड़ड़ले से इलाज कर रहे है।

मामले में झाबुआ जिले की ड्रग इंस्पेक्टर गीतम पथोडिया से माही की गूंज ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन ही नहीं उठाया।

इनका कहना है,

खवासा और भांमल में किसी के पास भी पंजीकृत सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही लेब वालों को परमिशन है। सब अवैध तरिके से चला रहे है, वरिष्ठ अधिकारी जैसे ही मार्गदर्शन देंगे उसके बाद उनके ऊपर कारवाई की जाएगी।

राकेश निनामा सीबीएमओ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खवासा ।

गांव में नहीं है पानी की निकासी, दुकानो में घुस रहा पानी

माही की गूंज नरेश पंचाल, काकनवानी।

ग्राम पंचायत काकनवानी के ग्रामवासी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इस गांव मे कोई विकास होगा या नहीं यह तो भगवान ही जानता है। ग्रामवासी कई मुसीबत से गुजर रहे हैं गर्मी हो बारिश हो या ठंड हो इन सभी मौसम में किसी न किसी कारणों से पंचायत की मेहरबानी से परेशान रहते है।

अभी बारिश का मौसम है और गांव में पानी की निकासी का कोई स्त्रोत नहीं है जिस कारण मंदिर से लगाकर ग्राम पंचायत तक और बाजार में कई जगह इतना पानी भर जाता है कि, लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। लोगों के घरों एवं दुकानों में भी पानी घुस जाता है सामान का नुकसान होता है। पंचायत में बैठे सरपंच-सचिव गांव की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके फल स्वरुप ग्राम वासियों को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है।

पूर्व में स्कूल के गेट एवं स्कूल के पास में पानी निकालने की जगह थी जो वर्तमान में एक बिल्डिंग बनी हुई है एवं पंचायत के पास में बने नाले से पानी की निकासी होती थी जहां नाला भी बंद हो गया और स्कूल के गेट पर आर सीसी करके ऊंचाई बढ़ा दी गई। जिस कारण से वहां भी पानी का घेराव होता है एवं स्कूल के पास में बड़ी बिल्डिंग भी बनी जिस कारण से गांव में पानी की निकासी बंद हो गई। अब ग्रामवासी क्या करें यह समझ के बाहर है।

आधे गांव में नहीं है गटर

गांव में बरसों पहले बाजार में और दोनों और गटर बनी हुई थी लेकिन धीरे-धीरे अतिक्रमण बढ़ता गया और गटर समाप्त होती गई। वर्तमान में बारिश एवं घरों के लेट बाथ का पानी रोड पर ही बह रहा है यह सब पंचायत की अनदेखी से गंदगी बढ़ रही है। 1 वर्ष पूर्व गटर के लिए पैसा निकाला गया लेकिन वह गटर भी गांव में नहीं बनी।

मच्छरों की हो रही भरमार

गांव में जगह-जगह पानी भरा होने से मच्छरों की भरमार हो रही है और उससे बीमारी भी फैल रही है। लेकिन पंचायती राज में सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरी जा रही है और कमाई में ही लगे हुए हैं। उन्हें गांव की जनता से कोई सरोकार नहीं है। पहले गांव में साफ सफाई कर दवाई का छिड़काव होता था एवं पीने के पानी में गोलिया डाली जाती थी। कुआँ बावड़ी एवं हैंडपंपों में बोरिंग में भी दवाई डाली जाती थी लेकिन मलेरिया विभाग का यह सारा कार्य बंद हो गया। अब यह कार्य पंचायत को देखना होता है कि गांव में साफ सफाई मच्छर, जगह-जगह गंदा पानी भरा हुआ, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है उसे दूर करें और गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। लेकिन यहां ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अस्पताल के पास से नाला गुजर रहा है जहां गंदगी ही गंदगी हो रही है और वही नाला मंदिर एवं स्कूल के पास से भी गुजर रहा है जिसकी भी सफाई नहीं हुई जिस वजह से भी महामारी फैलने का डर बना रहता है। गांव में गटर नहीं होने से गटर का पानी भी रोड पर बह रहा है गंदगी फैल रही है जिस पर भी पंचायत ध्यान नहीं दे रही।

आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं गांव वाले

गांव में सफाई का मामला हो या गटर का मामला हो या शुद्ध पेयजल का मामला हो, या नल जल का मामला हो, किसी भी प्रकार का पंचायत संबंधी कार्य हो और वह नहीं हो पा रहा है और ग्राम वासियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। जीवन भर इस संकटों का सामना करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार स्वयं के पैसों से खर्च कर अपनी जरूरत को ग्रामवासी पूरा कर रहे हैं। लेकिन ग्रामवासी ना तो सरपंच से कोई शिकायत कर रहा है और ना ही सचिव एवं ऊपर बैठे अधिकारी को या कलेक्टर को किसी प्रकार से शिकायत आवेदन भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि, ग्रामवासी यह सब चुपचाप सहन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये समझ से परे हैं।

घटिया सामग्री को लेकर कोटवारों का विरोध, ज्ञापन सौंप कर राशि खातों में देने की मांग

माही की गूंज, पेटलावद।

शिवराज सरकार से चली आ रही घटिया सामग्री सप्लाई की प्रथा मोहन राज में बदस्तूर जारी है और भ्रष्टाचार का खेल और बढ़ गया है। भ्रष्ट सप्लायर बड़े स्तर पर खेल, खेल कर अपना उल्लू सीधा कर रहै है। शिवराज सरकार में बच्चों की स्कूल ड्रेस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका ,आशा कार्यकर्ताओ को घटिया साड़ी सप्लाई और स्कूली बच्चो को खेल सामग्री के नाम पर घटिया खिलौने सप्लाई के बाद। अब मोहन सरकार ने राजस्व में कार्य कर रहे कोटवारों को दी जाने वाली ड्रेस ,जूते, बेल्ट की सप्लाई में भ्रष्टाचार देखने को मिला है। नाराज कोटवार संघ ने इसका कड़ा विरोध करते हुवे सीधे मिली सामग्री को घटिया और बिना मानक की बताते हुए सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार अनिल बघेल को देकर सामग्री के लिए राशि सीधे खाते में डालने की मांग की,जिससे शासन द्वारा बताई गई सामग्री और ड्रेस खुद खरीद सके।

बिना नाप ओर घटिया क्वालटी की ड्रेस

पूर्व में कोटवारों की ड्रेस नीले रंग की थी लेकिन शिवराज सरकार ने ड्रेस का रंग बदल कर खाखी कर दिया था। पूर्व में इनको ड्रेस के लिए राशि बैंक खातों में दी जाती थी। लेकिन इस बार कोटवारों को आगे से ही ड्रेस दी जा रही है। ड्रेस की हालत और कपड़े की क्वालिटी देख कर ही पता चलता है कि, पूरा खेल बड़े स्तर पर पूरे मध्यप्रदेश में सप्लाई और कमीशन का खेल है। बिना नाप और हल्की क्वालटी की ड्रेस मिलने से कोटवारों में भारी नाराजगी देखी गई। ड्रेस के साथ मिलने वाले टोपी,जूते ओर बेल्ट की क्वालिटी भी हल्की है ।

धर्मांतरण भारतीय संस्कृति के लिए घातक

माही की गूंज,झाबुआ।

भारतीय संस्कृति के लिए धर्मांतरण किस स्तर तक घातक है उसका मुल्यांकन उस देशों या उन स्थानों का देखकर किया जा सकता है जहां धर्मांतरण के बाद सबकुछ बदल गया। धर्म बदलने के बाद व्यक्ति की विचारधारा पूर्णतहः बदल जाती है वह भारत के प्रति श्रृद्धेय न होकर विदेशी मुल्क या विदेश से संचालित धर्म के प्रति सोच रखने वाला हो जाता है और नतमस्तक भी वह उन्हीं की ओर होता है। स्वेच्छा से धर्म बदल लेने या अपने मत को परिवर्तन कर लेने के किस्से बहुत ही कम है परंतु जोर जबरदस्ती, लालच, प्रलोभन, धोकाधड़ी, झुठ बोलकर भोलेभाले लोगों का धर्मांतरण करने के इस पूरे देश में अनगिनत मामले हैं। देश ही क्या पूरे विश्व के इतिहास को खंगाला जाए तो अनगिनत मामले ऐसे सामने आ जाएगे जिसमें बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव और प्रलोभन, मिथ्या, माया, लोभ और मार काट के माध्यम से ईसाई मिशनरी और मुस्लिम समाज ने धर्मांतरण किया है।

धर्म युद्ध धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है किंतु विदेशी पंथों, मतो ने षड़यंत्रपूर्वक भारत में मतांतरण और धर्मांतरण का जाल फैलाया और लोगों का धर्म छुड़वाकर अपने पंथों में लाकर उन सभी को भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विचार, से दूर कर दिया। ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों ने ही इसे धर्म युद्ध से जोड़ लिया अतः ईसाई इस धर्म युद्ध को क्रुसेड कहते हैं और मुस्लिम इस युद्ध को जिहाद कहते हैं, जबकि देखा जाय तो ये कोई धर्म युद्ध है ही नहीं।

इतिहास साक्षी है कभी किसी भारतीय हिंदु ने धर्म को बढ़ाने के लिए कभी कोई युद्ध नहीं किए, न ही कभी किसी को प्रलोभन देकर सनातन धर्म में लाया गया, और न ही कभी मारकाट करते हुए किसी को सनातन संस्कृति में आने के लिए विवश किया। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि विश्व में अनेक पंथ या मार्ग है जो मुझ तक ही पहुंचते है। व्यक्ति उन मार्गों को चुनकर दूसरो पर परोपकार करते हुए परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। परंतु धर्मांतरण करवाने वालों द्वारा तो जबरन धर्म को थोपकर किसी अन्य मार्ग पर ही चलाया जाता है।

एक संत द्वारा कहा गया था कि, धर्म के प्रचार के लिए भारत में जिस तरह छुट दे दी गई थी ठीक उसके अनुरुप किसी धर्म का प्रचार किया जा सकता है मगर उस प्रचार को माध्यम बनाकर किसी को भी लोभ, मोह, बल, मिथ्या से उस पंथ में नहीं लाया जा सकता है। यदी आपके धर्म में लाने के लिए किसी को भी लोभ, मोह, बल, मिथ्या को प्रयोग करना पड़ रहा है तो फिर उस पंथ की परिपक्कता का क्या परिमाण और ऐसे पंथ का क्या परिणाम। फिर यदी किसी का पंथ या मत या फिर मजहब महान है तो उनमें लाने के लिए इतनी मश्कत क्यूं करनी पड़ती है।

भोलेभाले लोगों को बहला फुसला कर मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, रोजगार, का लालच देकर विदेशी धर्म के लोगों ने धर्मांतरण का खेल अभी कुछ समय से नहीं बल्कि कई सदीयों पहले से चलाया था। पहला क्रुसेड 1096 से 1099 तक तक था इसी दौरान मुस्लिम दश्मिक में एकत्र हुअ और पहली बार अरबी भाषा के शब्द जिहाद का उपयोग किया। सांतवी शताब्दी में व्यापारी बन कर मुस्लिम भारत में आए, मुसलमानों ने अधिक मात्रा में कत्लेआम कर बहुत से भू भाग पर कब्जा किया वहां के हिंदु पलायन कर गए, और जो नहीं जा पाए वो भय के कारण मुसलमां बन गए। सुफी संतों ने धोका देकर मतांतरण करवाया उन्हेंने इस्लाम को बदनाम भी किया, क्योंकि लोग आध्यात्म के कारण उनके पास चले जाते थे किंतु बाद में पता चलता कि वे मुस्लिम शासकों के लिए जासूसी करते थे। 12वीं शताब्दी तक मुस्लिम भारत में पूरी तकह से प्रवेश पा चुके थे। जानकार बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के 70 प्रतिशत मुस्लिम ब्राह्मण है इसका खुलासा एक डीएनए रिपोर्ट में हुआ था।

रिकेश बैरागी

ईसाई समुदाय ने भी भारत में निवास कर रहे लोगों की निर्धता का लाभ उठाते हुए धर्मांतरण का षड़यंत्र फैलाया और 72 ईस्वी में पहला ईसाई व्यक्ति थॉमस को भारत भेजा, जिसने पहला निशाना जनजाति समुदाय के लोगों को बनया। फिर 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर ने रोमन केथोलिक ईसाई समुदाय की स्थापना की और निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, नोकरी, का लालच देकर लाखों हिंदुओ को ईसाई पंथ की तरफ मोड़ दिया। अमेरिकन वेद के लेखक फिलिप गोल्डबर्ग के अनुसार अशिक्षित और असहाय हिंदुओ को बल, झुठ, प्रलोभन देकर ईसाई बनाया गया। जो कि वर्तमान में भी जारी है।

धर्मांतरित व्यक्ति भारत के विचारों को छोड़ देता है, वो भारतीय संस्कृति को त्याग देता है, उसके साथ ही उसका पूरा परिवार भारत की वर्षो वर्ष प्राचीन सभ्यता से दूरी बना लेता है, और वह उन विदेशी विचारों पर श्रृद्धा रखता है जो भारतीय संस्कृति को हर संभव प्रयास से समाप्त करने की सोच रखते हैं। भारतीय संस्कृति सभ्य होने के साथ-साथ पूर्णतः वैज्ञानीक दृष्टीकोण रखने वाली है और मनुष्य प्रजाति को योग, ध्यान के बल पर मष्तिष्क के सर्वोच्च शिखर पर ले जा सकती है। इतनी शक्तिशाली भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए विदेशी शक्तियां सदीयों से लगी हुई है जिसके परिणाम घातक ही सामने आए है। भारतीय संस्कृति को भय और खतरे से बाहर करने के लिए धर्मांतरण जैसे घातक प्रहार से बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर सटीक प्रयास करना चाहिए साथ ही साथ सरकार को भी धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़े, कठोर दंड वाले कानून लाने चाहिए ताकी धर्मांतरण करने वालों की शक्ति नष्ट हो ताकि वे भारत में धर्मांतरण का कोई नया खेल खेले।

बहरहाल, उत्तर प्रदेश में एक सुफी संत छांगुर बाबा के धर्मांतरण के खेल का भांडा फोड़ दिया गया है जिसे विदेशो से मुस्लिम पक्ष में धर्मांतरण करने पर 100 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। उस राशि का उपयोग अलग-अलग प्रकार के जिहाद करने के लिए किया जाता था। युपी प्रशासन ने सख्त रुख लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

हाय रे ये शिक्षा विभाग...

निजी स्कूलों की मान्यता का फर्जीवाड़ा कक्षा में सुखाए जा रहे अंडर गारमेंट

मान्यता में कुल 14 कक्ष लेकिन 2 ही कक्षो के हो रही बिना खेल मैदान के स्कूल संचालित।

चौकोर घेरे में स्कूल कक्ष में सुखा रखी माड़साब ने अपनी अंडरवियर। यानी की माड़साब के रहने वाले 2 कक्ष उसी में हो रही स्कूल संचालित।

डीपिसी की मान्यता व मोके पर हो संचालित निजी स्कूल में बड़ा झोल।

माही की गूंज, खवासा।

एक शिक्षा ही है जो हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाती है, वही हमारा एमपी अजब और गजब ही है। यहां का शिक्षा विभाग व शिक्षा देने वाले हमारे विद्धयमान अधिकारी शिक्षा के मंदिर उर्फ निजी स्कूलों की मान्यता धरातल पर कुछ और। तो जवाबदारों के निरीक्षण के साथ मान्यता प्रमाणपत्रों पर कुछ और ही दर्शा रहे हैं। यानी कि चन्द रूपयो की लालच उर्फ रिश्वतखोरी के चलते फर्जी मौका मुआयना दर्शाकर निजी स्कूलों की मान्यता के नाम पर खुल्लेआम फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और संबंधित विभाग के विद्धयमान अधिकारी फर्जी रूप से मान्यता देकर हर किसी को बेवकूफ या अंधे ही समझ रहे हैं। जो कहीं न कहीं हमारे देश के भविष्य विद्यार्थियों के साथ छलावा व अनैतिक शिक्षा का माध्यम बन रहे हैं। झाबुआ जिले के थांदला विकासखंड के अधीन जिले की सीमा की अंतिम पंचायत माही किनारे ग्राम पंचायत तलावड़ा में सामने आया।

ग्राम तलावड़ा में सड़क किनारे एक किराये के मकान में सरस्वती ज्ञान मंदिर तलावड़ा के नाम से जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र झाबुआ ने माध्यमिक स्कूल की मान्यता प्रदान की गई। मान्यता प्रतिवेदन में कुल 16 बिंदुओं में मापदंड दर्शाए गए है। जिसमें अंतिम बिंदु 16 वे नंबर पर दर्शाया गया है कि, अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी। लेकिन नियम का पालन व अनियमित्ता होने पर क्या उक्त निर्देशों का पालन होगा...? यह बड़ा प्रश्न है।

गूंज को ग्रामिणो की शिकायत

माही की गूंज कार्यालय में उक्त स्कूल की फर्जी मान्यता के संबंध में ग्रामीणों ने आकर शिकायत के साथ जानकारी दी। ग्रामीणों ने बताया कि, डीपीसी द्वारा जारी मान्यता में स्कूल आईडी पीएस 123186 सरस्वती ज्ञान मंदिर तलवाड़ा, अध्यक्ष दशराज त्रिपाठी, जन कल्याण समिति राणापुर को 9 अप्रैल 2025 को कक्षा 8 वीं माध्यमिक स्कूल तक 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक मान्यता हेतु प्रतिवेदन जारी किया।

उक्त स्कूल संचालक जिले के नहीं होकर बाहरी क्षेत्र के हैं तथा फर्जीवाडे के साथ डीपीसी द्वारा मान्यता दी गई के आरोप लगाए गए। मान्यता प्रतिवेदन में बिंदु नंबर 10 पर उल्लेखित है कि, स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदंड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गई।

जो की 14 कालम में स्कूल की मान्यता के मुख्य मापदंड एवं स्कूल भवन निर्माण के संबंध में दर्शाए गए हैं।

कालम नंबर 1. स्कूल के भवन की स्थिति - किराए का भवन, 2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल - 32 सौ स्क्वायर फिट, 3. कुल निर्मित क्षेत्रफल - 2 हजार स्क्वायर फिट, 4. खेल मैदान का क्षेत्रफल - 12 सौ स्क्वायर फिट, 5. कक्षाओं के कमरों की संख्या-10, 6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष - 3, 7. लड़कों व लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन - हाँ, 8. स्वच्छ पेय जल सुविधा - हाँ, 9. मध्याहन भोजन के लिए रसोई घर - 1, 10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा - हाँ, 11. पठन-पाठन सामग्री - हाँ, 12. खेल एवं खेलकूद उपकरण - हाँ, 13. पुस्तकालय की उपलब्धता -हाँ, 14. शिक्षकों की संख्या 8 दर्शाई गई है।

जबकि उक्त 14 कालम में क्रमांक 1 किराये का भवन है यह सत्य है। बाकी 13 कालम में दर्शाए आंकड़े, भवन कक्ष, प्रधान अध्यापक कक्ष व सह कार्यालय कक्ष, मध्याहन भोजन के कक्ष या 8 शिक्षक या बाधा रहित प्रवेश की सुविधा यह एक मिथ्या ही है। क्योंकि मौके पर स्कूल सड़क किनारे ही संचालित हो रही है। जिसमें मात्र दो कक्ष है। प्रसाधन की सुविधा पृथक नहीं है। खेल मैदान है ही नहीं। ऐसे में जहां सर्व सुविधा के साथ खेल मैदान एवं स्कूल 14 कमरों के साथ डीपीसी के निर्देशन में बीआरसी टीम से करवाया गया निरीक्षण के साथ दी गई मान्यता में मात्र दो कक्ष में स्कूल संचालित हो रही। उक्त स्कूल में 100 से अधिक विद्यार्थी का प्रवेश के साथ उक्त फर्जी निरीक्षण के साथ मान्यता वाली स्कूल में प्रवेश अभी भी चालू है।

उक्त स्कूल में वर्तमान में 4 शिक्षक है जो की छतरपुर जिले के बताए जा रहे हैं। इतना ही नही माही की गूंज को मिले फोटो में स्कूल कक्ष में माड़साब की अंडरविअर को केसे सुखाया जाता है यह भी शायद बच्चो को यह 4 शिक्षक सिखा रहे है। तभी तो स्कूल कक्ष में ही शिक्षको ने अंडरविअर सुखा रखी है जो फोटो में भी दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि, मौके पर जीपीएस लोकेशन के साथ डीपीसी एवं उनके अधीन बीआरसी टीम ने निरीक्षण किया होगा और जो 14 कक्ष व खेल मैदान मान्यता में दर्शाए गए हैं वो मान्यता वाली सुविधा आकर हमें बताएं। अन्यथा 2 कक्ष वाली व स्कूल कक्ष में माड़साब की चड्डी सुखाने वाली उक्त स्कूल की फर्जी मान्यता रद्द की जाए। क्योंकि जो स्कूल संस्था झूठे मापदंडों को दर्शाकर भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर फर्जी मान्यता प्राप्त करती है वे हमारे बच्चों को सही शिक्षा व सही मार्गदर्शन कैसे दे पाएगी...?

दो बाईक की भिड़ंत

माही की गूंज, भामल।

ग्राम के रूपारेल घाटी पर सोमवार रात्रि में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। उक्त दुर्घटना में दोनों बाईक चालकों को चोट लगी। घटना के बाद ग्रामिणो की मदद से 108 एंबुलेंस के माध्यम से घायलो को पेटलावद सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। खवासा चौकी प्रभारी एडमिरल तोमर ने बताया कि, दोनों वाहन चालकों की रात्रि में आमने-सामने भिड़ंत हुई जिनका पेटलावद अस्पताल में इलाज चल रहा है।

गुरु पूजा के लिए मंदिरों में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, कई जगहों भंडारों के आयोजन

विशेष संयोगों के साथ शुरू होगा सावन माह, रहेंगे कुल 4 सावन सोमवार

माही की गूंज ,पेटलावद।

गुरु पूर्णिमा को लेकर जगह जगह तैयारियां शुरू हो गए हैं। नगर के साईं मंदिर पर होने वाले भव्य जुलूस एवं भंडारे की तैयारीया जोरो पर है साथ ही क्षेत्र के कई मंदिरों पर गुरु पूर्णिमा के लिए मंदिरों पर भव्य साज सज्जा की गई ,पेटलावद के समीप ग्राम दुलाखेड़ी स्थित हनुमान मंदिर पर श्री 1008 ब्रह्मलीन भगवान दास फ़लिहारी महाराज की गुरु पूजन के साथ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार प्राचीन तपस्थली श्रग्रेश्वर धाम झकनावदा में सद्गुरु श्री 1008 ब्रह्मलीन श्री काशिगिरी बाबा की तप स्थली पर गुरु पूर्णिमा पर विशेष आयोजन रखा गया है। यहां पेटलावद क्षेत्र सहित जिले और धार, राजगढ़ क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन हेतु पहुँचते है। मंदिर समिति सदस्य अभय बोहरा ने बताया कि बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं आज सुबह गुरु पूजन और महाअभिषेक किया जाएगा जिसके बाद महाआरती और महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया जाएगा।

इस बार सावन में होंगे चार सोमवार

गुरु पूर्णिमा के साथ ही सावन माह की शुरुआत हो रही है। भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। सावन का महीना बेहद ही पवित्र माना जाता है। श्रावण मास शंकर भगवान को समर्पित होता है और भक्त देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा-आराधना करते हैं। इस महीने को भगवान शिव के प्रिय माह में से एक कहा जाता है। हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सावन आरंभ हो जाते हैं। इस बार सावन में कुल 4 सावन सोमवार पड़ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार होता है। पंडित नरेन्द्र नंदन दवे ने बताया इस महीने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। साथ ही मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार के व्रत का भी बहुत महत्व होता है। सावन सोमवार व्रत पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन माह का आरंभ श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ होता है। इसलिए श्रावण मास का आरंभ 11 जुलाई से हो रहा है। इसके साथ ही श्रावण पूर्णिमा यानी 9 अगस्त को सोमवार के दिन ही इसका समापन हो जाएगा।

स्कूल का जर्जर भवन तो वहीं अतिक्रमणकर्ता की बल्ले-बल्ले

गर्मी में किया था कलर बारिश में निकल गया - शिक्षिका

माही की गूंज, खवासा/भामल।

बिना रंगाई पुताई व देख रेख के अभाव में स्कूल भवन होते जा रहे जर्जर।

कहने को तो फलीये - फलीये में स्कूल है लेकिन ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की स्थिति बेहाल है। वही स्कूल भवनों की स्थिति देखरेख के अभाव में बेहाल ही है। कहने को तो प्रत्येक स्कूल भवनों के लिए प्रतिवर्ष स्कूल की माइनर मरम्मत व रंगाई-पुताई के साथ बच्चों को खेल-कूद हेतु सामग्री खरीदी के लिए निर्धारित राशि आवंटित होती है। लेकिन भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना चुके सिस्टम के तहत न ही स्कूल भवनों की मरम्मत होती है न ही कोई कलर किया जाता है। और न ही बच्चों के लिए कोई व्यवस्थित खेल सामग्री लाई जाती है। लेकिन कागजों पर यह सारे खर्च कर दिये जाते हैं। वहीं स्कूलों की जमीनों व उसके आगे या आस-पास अतिक्रमणकर्ता जमकर अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके कई उदाहरण देखे जा सकते हैं लेकिन जवाबदारो का ध्यान इस और भी नहीं है। जिसके चलते अतिक्रमणकर्ताओ कि बल्ले-बल्ले हैं।

भामल ग्राम पंचायत के ग्राम ढोलखड़ा की प्राथमिक स्कूल की बात करें तो यहां 41 विद्यार्थी दर्ज है। यहा की प्राथमिक स्कूल की आवंटित जमीन करीब ढाई बीघा जमीन है। उक्त आवंटित जमीन पर तीन स्कूल कक्ष व एक किचन सेट कक्ष बना हुआ है। उक्त भवन की समय पर रख-रखाव, मरम्मत नहीं करने व रंगाई - पुताई नहीं होने के चलते जर्जर अवस्था में पहुँच रहा है। वहीं उक्त स्कूल की बाउंड्रीवाल नहीं होने के चलते स्कूल की आवंटित भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओ ने अपना कब्जा जमा लिया है।

ग्रामीण कालू मेड़ा ने बताया कि, स्कूल की दो से ढाई बीघा जमीन आवंटित है। जिस पर एक किचन शेड के साथ तीन कक्ष बने हुए हैं। बाकी स्कूल की खाली पड़ी जमीन पर अतिक्रमणकर्ताओं ने अपना अतिक्रमण शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि, स्कूल की आवंटित भूमि का सीमांकन कर बाउंड्रीवॉल बनाई जाए। ताकि स्कूल की जमीन को अतिक्रमण कर्ताओं से सुरक्षित रखा जा सके।

वहीं ग्रामीणों का कहना ही कि, प्रतिवर्ष कहने को तो स्कूल भवन की मरम्मत व रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष राशि आवंटित होती है लेकिन मरम्मत तो ठीक स्कूल भवन का कलर तक नहीं करवाया जाता है। न ही कोई स्कूल पर शिक्षारत कोई स्लोगन लिखे गए हैं जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले और न ही मध्याहन भोजन मेन्यू चार्ट भी नहीं लिखा गया है।

उक्त कार्य प्रतिवर्ष रंगाई - पुताई के साथ ही संभव होता है। लेकिन उक्त स्कूल भवन पर पिछले दो-तीन वर्षों से न ही कोई रंगाई-पुताई की गई और न ही कोई मरम्मत का कार्य किया गया।

वही मामले को लेकर प्राथमिक विद्यालय ढोलखरा की प्रभारी शिक्षिका संगीता वसुनिया ने बताया कि, हमने गर्मी में ही कलर स्कूल भवन पर करवाया था लेकिन बारिश की वजह से कलर निकल गया। उक्त शिक्षिका की बात महज हास्यप्रद ही दिखाई दे रही है। जबकि यहां एक अशिक्षित व्यक्ति भी देखकर कह सकता है कि, नये सत्र के पूर्व गर्मी में भवन का कलर करवाना तो ठीक पिछले कई वर्ष से उक्त स्कूल भवन पर कोई रंगाई-पुताई नहीं की गई है यह कह सकता है।

वहीं दूसरी बात अतिक्रमण पर शिक्षिका ने बताया कि, उक्त स्कूल की कितनी भूमि आवंटित है या रिकॉर्ड में दर्ज है मुझे भी पता नहीं है मैं, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों से ही पूछकर कुछ बता पाऊंगी। यह बात सही है कि स्कूल के आस-पास अतिक्रमण हो रहा है।

चातुर्मासिक मंगल प्रवेश का भव्य कार्यक्रम

माही की गूंज, पेटलावद। श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के 11 वें आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या साध्वी श्री पंकज श्री जी आदि ठाणा 3 के पावन सानिध्य में स्थानीय तेरापंथ भवन में चातुर्मास प्रवेश के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपस्थित श्रावक समाज को सम्बोधित करते हुए साध्वी श्री पंकज श्रीजी ने कहा कि, चातुर्मास में तप,संयम,ओर साधना का अपना एक अलग ही महत्व होता है। चातुर्मास संयम,आत्मचिंतन ओर साधना के लिए होता है। इस अवसर पर साध्वी श्री शारदा प्रभाजी ने कहा कि हमे समय के साथ चलना है।बगल में देखने की बजाय स्वयं को देखने का प्रयत्न करना चाहिए।आपने कहा कि जो गुरुदृष्टि की आराधना करता है वह मोक्ष सुखों को प्राप्त करता है। उक्त गरिमामय कार्यक्रम में साध्वी श्री शालीनप्रभाजी ने अपनी मधुर आवाज में गीतिका के माध्यम से अपनी प्रस्तुति प्रदान की।कार्यक्रम का प्रारम्भ नमस्कार महामंत्र से किया गया। मंगलाचरण कन्या मंडल ने किया। इस अवसर पर स्थानीय तेरापंथ सभा अध्यक्ष नरेंद्र पालरेचा ने अपनी ओजस्वी शैली में स्वागत भाषण दिया व सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम में मालवा सभा अध्यक्ष संजय गांधी,महिला मंडल उपाध्यक्ष दीपा मूणत,तेयुप अध्यक्ष अभिषेक पटवा,महासभा कार्यकारिणी सदस्य पंकज कोठारी,ज्ञानशाला प्रशिक्षिका हेमलता कोठारी,अणुव्रत समिति अध्यक्ष सचिन मूणत,कन्या मंडल संयोजिका प्रेक्षा मारू,तुलसी बाल विकास समिति व जय ट्रस्ट अध्यक्ष पारस गादिया सहित फूलचंद कांसवा, ज्ञानमल मूणत (रायपुरिया), प्रीति बोहरा (झकनावदा) ,राजेश वोरा,कीवी भंडारी आदि ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की। उक्त आयोजन में स्थानीय महिला मंडल की टीम ने सामूहिक रूप से गीतिका प्रस्तुत की। आयोजन में ज्ञानशाला के नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी सुंदर व सराहनीय प्रस्तुति दी। उक्त कार्यक्रम के पूर्व चातुर्मासिक प्रवेश पर तेरापंथ श्रावक समाज द्वारा स्थानीय खुश्बू गार्डन से लेकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एक विशाल रैली निकाली गई जो 'तेरापंथ भवन में धर्मसभा के रूप में परिवर्तित हुई। साध्वीवृन्द के मंगल प्रवेश पर आयोजित उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन करते हुए अभातेयुप सदस्य व सभा के मंत्री रूपम पटवा ने चातुर्मास काल मे पूरे श्रावक समाज से ज्यादा से ज्यादा धर्मलाभ लेने हेतु विशेष निवेदन किया। आभार अणुव्रत समिति के राज्य सह प्रभारी पवन भंडारी ने माना। इस अवसर पर सभा के मीडिया प्रभारी पंकज जे.पटवा ने उक्त गरिमामय कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि साध्वीवृन्द के चातुर्मासिक भव्य मंगल प्रवेश के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त गरिमामय कार्यक्रम में स्थानीय व पेटलावद क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं विशेष रूप से उपस्थित थे।

संपादकीय

हिमालयी परिवेश की रक्षा

हाल के दिनों में हिमालयी राज्यों खासकर हिमाचल व उत्तराखंड में अतिवृष्टि और बादल फटने की घटनाओं में जिस तेजी से पुनरावृत्ति हुई है, उसे मौसम के चरम के रूप में देखे जाने की जरूरत है। हालांकि, तात्कालिक जरूरत आपदा प्रभावित जिलों में राहत, बचाव व पुनर्वास के प्रयासों में तेजी लाने की है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत मौसम के चरम के बीच अचानक आती बाढ़ और बार-बार बादल फटने के कारणों को भी समझने की है। हाल ही में, इन्हीं मुद्दों की तरफ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ध्यान खींचा है। निस्संदेह, इन कारणों की पड़ताल के लिए विषय विशेषज्ञों की सहायता लेना भी जरूरी है। पिछले दिनों हिमाचल में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री ने उन उपायों की सूची पर चर्चा की, जिन्हें तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। इन उपायों में नदियों में अवैज्ञानिक तरीके से मलबा फेंकने की जांच, नियमित मौसम अपडेट देना और नदी-नालों से कम से कम सौ मीटर की दूरी पर घरों का निर्माण करना शामिल है। लेकिन इसके प्रभावी लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब इस बाबत किसी ठोस योजना को अमलीजामा पहनाया जाए और साथ ही नीतियों के क्रियान्वयन की समय सीमा निश्चित की जाए। निश्चित रूप से मौजूदा संकट को देखते हुए युद्धस्तर पर काम करने की जरूरत है। वह समय चला गया जब सरसरे आदेश दिये जाते और सिफारिशें की जाती थीं। कानूनों और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सभी एजेंसियों को तालमेल बैठाकर इस दिशा में अभियान चलाने की जरूरत है। वनों की अवैध कटाई, अनियोजित निर्माण और अवैज्ञानिक विकास प्रथाओं पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। इसके लिये सरकारी मशीनरी को मिशन मोड में काम करने की जरूरत होगी। जिसके लिये मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। भले ही राज्य की सत्ता में दो दलों का वर्चस्व हो और उनकी विचारधाराओं में टकराव रहा हो, लेकिन इस मुद्दे पर एकजुट होकर संकट का मुकाबला करने की जरूरत है।

निश्चय ही हाल के वर्षों में पहाड़ विरोधी विकास ने हिमालयी राज्यों की अस्मिता को आहत किया है। हिमालयी राज्यों में लोग पहाड़ों के मूल चरित्र में हस्तक्षेप करने वाले विकास की विसंगतियों की कीमत चुके रहे हैं। अब चाहे बड़े बांध हों या फोर लेन सड़के हों। निस्संदेह, विकास हर राज्य की प्राथमिकता है, लेकिन विकास योजनाओं को पहाड़ों की जरूरत के मुताबिक बनाया जाना चाहिए। इन राज्यों में स्थितियां विकट हैं और हालात और खराब होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भूस्खलन की लगातार बढ़ती घटनाएं और दरकती सड़कें इसकी बानगी मात्र हैं। कुल मिलाकर पहाड़ों के अस्तित्व पर संकट बढ़ा है। निस्संदेह, मौजूदा रणनीति और नीतियां इस संकट से निबटने में सक्षम नहीं हैं। सत्ता में बैठे लोगों के लिये जरूरी है कि वे मौसम विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों और क्षेत्र के अनुभवी लोगों से राय लें। साथ ही तकनीकी समाधानों को वरीयता दी जाए। इसमें दो राय नहीं कि मानव जनित समस्याओं के निदान के लिये मानवीय दृष्टि से संवेदनशील समाधान तलाशने की जरूरत है। निश्चित रूप से इसमें समुदाय के तौर पर एकजुटता के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह जाता। समय आ गया है कि हम एक बार फिर से पहाड़ों के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं। पहाड़ हमारी आवश्यकता तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन वे इंसान की विलासिता का बोझ सहन करने को तैयार नहीं हैं। निश्चित ही आधुनिकता की आंधी में संयम का जीवन और आवश्यकताओं को सीमित करना कठिन कार्य है, लेकिन बचाव का संभवत: अंतिम उपाय यही है। बहुमंजिला इमारतों को सीमित करना, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और निर्माण से पहले जमीन की क्षमता का आकलन करना जरूरी हो जाता है। नदियों में होने वाले अवैध खनन को रोकना भी उतना जरूरी है, जितना जंगलों का कटान रोकना जरूरी है। पहाड़ों को उस हरीतिमा से ढकना होगा जो भूस्खलन व मिट्टी के कटाव को रोकने में सक्षम हो। साथ ही नदियों के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करने वाले कारकों को दूर करने की भी जरूरत है। दरअसल, नदियां अधिक जल प्रवाह होने पर हमेशा अपने विस्तार क्षेत्र को ही तलाशती हैं।

किसानों को विवशता की हद से मुक्त कराएं

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक छोटा-सा वीडियो वायरल हुआ था। आपने भी देखा होगा एक बूढ़ा किसान बैल बनकर अपने खेत को जोत रहा है। उसे कितनी ताकत लगानी पड़ रही है इस काम में, इसका अहसास उसके चेहरे को देखकर अनायास ही हो जाता है। उसके पीछे से टेका देने का काम उसकी बूढ़ी पत्नी कर रही है। यह चित्र लगभग 70 वर्षीय किसान अम्बादास पवार और उसकी पत्नी का है। चार बीघा जमीन है दोनों के पास। पर हल चलाने के लिए बैल खरीदना उसके बस की बात नहीं है। इसलिए वह खुद बैल बन गया है!

ज्ञातव्य है कि यह दृश्य उस महाराष्ट्र का है जिसकी गणना देश के विकसित राज्यों में होती है। ज्ञातव्य यह भी है कि देश में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं में महाराष्ट्र के किसानों की संख्या सर्वाधिक है- पिछले तीन महीनों में अर्थात् अप्रैल, मई, जून, 2025 में महाराष्ट्र में 767 किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है! पिछले दस सालों में यह आंकड़ा औसतन प्रतिदिन दस आत्महत्याओं का पड़ता है। पचपन साल पहले देश में हरित क्रांति हुई थी। यह एक सच्चाई है। कृषि क्षेत्र में हमारे कृषि वैज्ञानिकों और हमारे किसानों ने 1970 में इस सच्चाई को साकार किया था। लेकिन यह सच्चाई जितनी मीठी है, उतनी ही कड़वी यह सच्चाई भी है कि हरित क्रांति के बावजूद हमारे किसानों की हताशा के फलस्वरूप देश में होने वाली आत्महत्याओं की संख्या लगातार डरावनी बनी हुई है। किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं का यह शर्मनाक सिलसिला हरित क्रांति के चार-पांच साल बाद ही शुरू हो गया था!

इसका कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है, यह एक खुला रहस्य है कि कृषि क्षेत्र में विकास के सारे दावों के बावजूद अधिसंख्य किसान अभावों की जिंदगी ही जी रहे हैं। इस दौरान बड़े-बड़े दावे हुए हैं किसानों के विकास के। करोड़ों-करोड़ों रुपया कथित 'खुशहाल किसानों' की तस्वीर दिखाते विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है; हर किसान का बैंक खाता होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि विज्ञापनों की सच्चाई और स्थिति की भयावहता कुछ और ही वर्णन कर रही है। यदि हमारा अन्नदाता सचमुच समृद्ध होता जा रहा है तो फिर देश की अस्सी करोड़ आबादी मुफ्त अनाज लेने के लिए विवश क्यों है? इस मुफ्त अनाज को भले ही कुछ भी नाम दिया जाये, पर हकीकत यही है कि सरकार के सारे दावों और वादों के बावजूद देश का औसत किसान आज भी ऋण में पैदा होता है, ऋण में जीता है और ऋण में ही मरने के लिए शापित है। यह शाप कब दूर होगा?

किसानों की दुर्दशा के जो कारण बताये जाते हैं, उनमें सबसे पहला स्थान ऋण का ही है। साहूकारों से, बैंकों से और अन्य सरकारी एजेंसियों से हमारा किसान ऋण लेता है। और यह ऋण समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता! जिन्हें ऋण मिल जाता है, उनकी जिंदगी उसे चुकाने में ही कट जाती है। यहीं इस बात को भी रेखांकित किया जाना

ज़रूरी है कि भारत का किसान उन उद्योगपतियों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार है जो बैंकों से अरबों का ऋण लेते हैं और या तो स्वयं को दिवालिया घोषित कर देते हैं या फिर विदेश में कहीं ऐसी जगह पर बस जाते हैं जहां से उन्हें भारत प्रत्यर्पित करना आसान नहीं होता। अरबों-खरबों के इन देनदारों को इस बात से भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें बेईमान कह रही है। उनकी तुलना में हमारा किसान कहीं अधिक शर्मदार है। ऋण न चुका पाने की स्थिति में वह शर्म से गड़ जाता है। आंख नहीं उठती उसकी। राजेश रेड्डी का एक 'शे'र' है, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं/ मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं'। यह 'मैं' भारत का वह किसान भी हो सकता है जो शाम को खाली हाथ घर जाने के लिए विवश है। वह मजदूर भी हो सकता है जो बच्चों की मुस्कुराहट को ही भूल जाता है। निराशा उसके दिमाग में पलने लगती है और हताशा हर शाम उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। और फिर... किसी एक दिन यह हताशा और निराशा, आत्महत्या बनकर दुनिया के सामने आ जाती है। इसमें थोड़ा-सा हिस्सा उस शर्म का भी होता है जो ऋण न चुका पाने की किसान की पीड़ा से उपजती है।

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी सवाल का जवाब भी नहीं है। मदद के लिए किसी हताश व्यक्ति का अंतिम चीत्कार ही कहा जा सकता है इसे। लेकिन यह कतई ज़रूरी नहीं है कि स्थितियां इस मोड़ तक पहुंचने दी जाएं। स्थितियों को बदलने का एक रास्ता लातूर के किसान अम्बादास और उनकी पत्नी ने दिखाया है। यह सही है कि बैल बनकर खेत जोतना समस्या का समाधान नहीं है। इसे विवशता की पराकाष्ठा के रूप में ही स्वीकारा जा सकता है। नहीं आनी चाहिए ऐसी नौबत कि किसी बूढ़े अम्बादास को अपना खेत जोतने के लिए बैल बनना पड़े। लेकिन इसे मनुष्य की कुछ भी कर सकने की क्षमता के रूप में भी देखा जा सकता है। कोई अम्बादास यह भूमिका निभाने के लिए विवश हो यह स्वयं उसके लिए नहीं, उस समाज और व्यवस्था के लिए भी शर्म की बात है जिसमें अम्बादास जी रहा है।

अम्बादास की विवशता के लिए उस व्यवस्था को जवाब देना होगा जिसमें वह जी रहा है। बैल बने किसान की मदद के लिए कोई सोनू निगम आगे आया है, यह बात कुछ दिलासा देने वाली है। सोनू निगम ने अम्बादास के बैंक खाते का नंबर मांगा है, ताकि बैल खरीदने की राशि भेजी जा सके। यह

विश्वनाथ सचदेव

किसी एक अम्बादास की समस्या का आंशिक हल हो सकता है, पर सवाल लाखों अम्बादासों का है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में कृषि-क्षेत्र से जुड़े लगभग ग्यारह हज़ार किसानों और कृषि मज़दूरों ने आत्महत्या की थी। सन् 2014 में यह संख्या 5650 आंकी गयी थी। इन आत्महत्याओं के लिए मानसून की असफलता, कीमतों में वृद्धि, ऋण का बोझ आदि को उत्तरदायी बताया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के दरवाजे पर हज़ारों किसानों का साल भर तक प्रदर्शन करते रहना सारी दुनिया ने देखा था। तब कृषि-कानूनों को वापस लेकर एक तरह से किसानों की मांगों को उचित ही ठहराया गया था। वे मांगें अभी भी पूरी नहीं हुईं।

इस बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में किसान अपनी मांगें मंगवाने के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि न तो साल भर के धरने ने सरकार को कुछ सार्थक करने की प्रेरणा दी और न ही किसानों की आत्महत्याएं सरकार के लिए किसी प्रकार की चेतावनी बन रही हैं। शायद अम्बादास के बैल बनने की विवशता से सरकार की नींद खुले।

बरसों पहले एक फिल्म आयी थी 'मदर इंडिया' इसमें नायिका को अम्बादास की तरह ही हल खींचते हुए दिखाया गया था। बचपन में देखी फिल्म का वह दृश्य आज भी आंखों में आंसू ला देता है। उम्मीद ही की जा सकती है कि उस फिल्म की यह पुनरावृत्तिदृअम्बादास का हल जोतनादृकहीं न कहीं ज़िम्मेदारी का भाव जगायेगी; आत्महत्या के लिए विवश किसानों के लिए कहीं कोई आंख नम होगी। पिछले पचपन साल से चल रहा आत्महत्याओं का यह सिलसिला हर कीमत पर बंद होना चाहिए। यह मामला राष्ट्रीय शर्म का है, पर 'शर्म उनको मगर नहीं आती' जिन्हें आनी चाहिए।

एफ - ३५ हुआ मंदा तो चल गया धंधा

ब्रिटेन का परम शक्तिशाली, एडवांस्ड टाइप का लड़ाकू जहाज एफ-35 त्रिवेंद्रम में क्या फंसा, लोग मौज लेने लगे। लड़ाकू जहाज अगर उड़ नहीं पाता, तो फिर उसका मजाक उड़ता है। एफ-35 का हाल भी ऐसा हुआ। केरल टूरिज्म ने तो फुल मार्केटिंग मौज ले ली। केरल टूरिज्म वालों ने ऐसे फोटो चला दिये, जिसमें एफ -35 कह रहा है कि केरल इतनी शानदार जगह है कि जाने का मन नहीं कर रहा है। एक फोटो में एफ-35 जहाज शराब जैसे पेय ताड़ी पीता हुआ दिखाया गया है, बस ताड़ी पीकर थोड़ा-सा डांस और कर लेता, तो मजा ही आ जाता।

यूं भी कहा जा सकता था कि यह एफ-35 पुराने शायर हजरत दाग का हवाई अवतार है। दाग साहब का शे'र थाकृहज़रत-ए-दाग़ जहां बैठ गए बैठ गए और होंगे तिरी महफ़िल से उभरने वाले दाग साहब जहां बैठ गये, वहां बैठ गये, आसानी से न उठने वाले।

एफ-35 के ठप होने का वाकया अद्भुत है। बस रुक जाती है, कार रुक जाती है। सब चल निकलती हैं। पर एफ-35 के नखरे ही कुछ और रहे। एफ-35 का अंदाज लखनवी नवाब का सा रहा, मन नहीं कर रहा है, तो नहीं उठे। जहाज नवाबी स्टाइल में काम करने लगे तो आफत हो जाती है। मतलब यह न हो कि एफ-35 कभी आसमान में उड़े दुश्मन पर बमबारी करने को और आसमान में जाकर दुश्मन जहाज से नवाबी अंदाज में कह उठेदृ जी पहले आप, पहले आप, पहले आप मार दीजिये।

एक अद्भुत कल्पना यह है कि जब भी लड़ाई का वक्त हो, दुनिया भर के सारे लड़ाकू जहाज ठहरायमान हो जायें। ठप हो जायें, चले ही नहीं। फिर जंग नहीं होगी। वो दुनिया बहुत सुंदर होगी जिसमें सफाई वाले ट्रक स्पीड से चलें, और लड़ाकू जहाज ठप रहें। अभी उलटा है। हमारे शहर में सफाई वाले ट्रक ठप रहते हैं। ट्रक क्या सफाई की पूरी व्यवस्था ही ठप रहती है। आधे घंटे की बारिश में एक हफ्ते तक नाली का रूपांतरण मिनी नदी में हो जाता है।

आलोक पुराणिक

वैसे मुझे लड़ाकू जहाज की तकनीक के बारे में ज्ञान नहीं है। पर कुछ देसी भारतीय तकनीक कमाल की होती हैं। जैसे हमारे शहर में अगर कोई गाड़ी बंद पड़ जाये, तो कई लोग उसके पीछे से धक्का लगाते हैं और वह चल निकलती है। क्या ही सुंदर निपट भारतीय दृश्य होता, जिसमें हम देखते कि एफ-35 के पीछे कई लोग धक्का लगा रहे हैं और एफ-35 स्टार्ट होकर उड़ गया।

एफ-35 पर इतनी खबरें आयीं कि वह अब इस देश की चेतना में गहरे धंस गया है। दिखावा-प्रिय अमीर लोग अब अपने परिवार की शादियों में पंडाल बनवायेंगे एफ-35 स्टाइल का।

अभी तो मुंबई के सीरियल वालों का ध्यान गया ही नहीं एफ-35 की तरफ। वरना अब तक तो सीरियल आ जाना चाहिए था।

संतुलित समाज के निर्माण में हो सहायक

जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, तो अक्सर महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तीकरण पर ज़ोर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही और आवश्यक भी है। लेकिन, इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू अक्सर छूट जाता है- पुरुषों के अधिकार और उन्हें न्याय दिलाने की आवश्यकता। अब हमारे समाज में पुरुषों के अधिकारों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी खुलकर बात होने लगी है। इसी कड़ी में एक पुरुष आयोग बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। पुरुषों का तर्क है कि उनके लिए भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे। यह लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम है। समाज में लिंग-आधारित रूढ़िवादिता के कारण, पुरुषों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने में हिचकिचाहट होती है, जिससे उनकी समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं।

लंबे समय से, घरेलू हिंसा और प्रेम संबंधों में होने वाली क्रूरता को अक्सर महिलाओं से जोड़कर देखा जाता रहा है, जो कि बिल्कुल सही भी है। महिलाएं इन अपराधों का शिकार होती हैं। लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि पुरुष भी इन अपराधों के शिकार हो रहे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां प्रेम संबंधों में अनबन या अन्य कारणों से पतियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। इन घटनाओं में, पुरुषों को न केवल शारीरिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उन्हें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और उनके पास मदद या शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई खास मंच नहीं है।

झूठे आरोप भी एक गंभीर समस्या है जिससे पुरुष जूझते हैं। दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों के झूठे आरोप पुरुषों के जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, भले ही वे बाद में निर्दोष साबित हो जाएं। यह उनके करिअर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। वर्तमान कानूनी ढांचे में, ऐसे मामलों में पुरुषों को खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अक्सर लंबा और जटिल संघर्ष करना पड़ता है, और उनके लिए कोई विशेष सहायता प्रणाली नहीं है।

इसके अलावा, दहेज उत्पीड़न या बलात्कार जैसे कानूनों का कई बार दुरुपयोग होता है, जिसके चलते कई निर्दोष पुरुषों को झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। पारिवारिक विवादों, जैसे तलाक या बच्चों की कस्टडी के मामलों में भी, अक्सर पुरुषों को अलग-थलग महसूस कराया जाता है और उनके पक्ष को कई बार उचित महत्व नहीं मिलता। मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है; समाज का दबाव पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता है, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में उन्हें न्याय पाने और अपनी बेगुनाही साबित करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह उनके करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। यही कारण है कि आत्महत्या के मामलों में भी पुरुषों की संख्या अक्सर अधिक पाई जाती है, जो उनके अंदरूनी संघर्षों को दर्शाती है।

ऐसे मामलों में अक्सर पुरुषों के प्रति समाज की

प्रतिक्रिया उतनी संवेदनशील नहीं होती जितनी महिलाओं के प्रति होती है। 'मर्द को दर्द नहीं होता' जैसी धारणाएं और सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपनी पीड़ा व्यक्त करने से रोकती है। उन्हें डर होता है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, उन्हें डर होता है कि समाज उनका उपहास करेगा या उन्हें कमजोर समझेगा। इसी वजह से कई बार वे अपनी समस्याओं को छिपाते रहते हैं, जो अंततः गंभीर परिणामों का कारण बनता है।

भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है, चाहे वे पुरुष हों या महिला। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की बात करता है और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। हालांकि, अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की छूट देता है, ताकि समाज में उनकी स्थिति सुधर सके। इसी आधार पर महिला आयोग और महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून बनाए गए हैं।

लेकिन क्या वास्तव में एक अलग पुरुष आयोग की आवश्यकता है? कुछ लोगों का मानना है कि मौजूदा कानूनी ढांचे में ही पुरुषों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और लिंग-विशिष्ट आयोग बनाने से समाज में और अधिक विभाजन पैदा हो सकता है। हालांकि, यह भी सच है कि पुरुषों की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। निःसंदेह, यदि एक पुरुष आयोग बनता है, तो यह केवल पुरुषों के लिए ही नहीं, बल्कि एक संतुलित समाज के निर्माण में भी सहायक हो सकता है। यह आयोग पुरुषों को जागरूक कर सकता है कि वे अपनी समस्याओं को कैसे उठाएं और समाज में सकारात्मक भूमिका निभाएं। यह लैंगिक समानता में सहायक होगा।

डॉ. सुधीर कुमार

उनका तर्क है कि पुरुष आयोग बनाना समानता के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों को भी उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए। यह एक ऐसी संस्था होगी जो पुरुषों से संबंधित डेटा एकत्र करेगी, उनकी शिकायतों को सुनेगी, और सरकार को उनके कल्याण के लिए सुझाव देगी।

हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, न्याय और गरिमा से वंचित न हो। यह समय है जब हम सभी लिंगों के सामने आने वाली जटिलताओं को पहचानें और एक ऐसा कानूनी और सामाजिक ढांचा तैयार करें जो सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। पुरुष आयोग की उठती आवाज़ इसी दिशा में एक चिंतन का विषय है, जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मोहर्रम के दिन विवाद, खूब चले थप्पड़-घूंसे, पुलिस ने किया कंट्रोल

माही की गूंज, शाजापुर।

नगर में मोहर्रम की 10 तारीख पर रविवार देर रात को विभिन्न मोहल्लों से दुलदुल के जुलूस और अखाड़े आजाद चौक में पहुंचे थे। यहां पर छोटा चौक में रखे सबसे बड़े दुलदुल को भी कंधों पर उठाकर आजाद चौक लाया गया। इसी दौरान समाज के दो गुटों के युवकों के बीच पुरानी बात को लेकर बहस के बाद गाली-गलौज और थप्पड़ मुक्के चलने लगे।

इससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर तैनात पुलिस ने तत्काल स्थिति को भांपते हुए बल प्रयोग करके उपद्र?वियों को खदेड़ा। इसके बाद सबसे बड़े दुलदुल की दौड़ एवं अन्य आयोजन को निरस्त करते हुए रात 2 बजे ही दुलदुल को इमामबाड़े में रखवाकर मोहर्रम का समापन कर दिया। हालांकि पूरे मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं कराई।

इस रूट पर जा रहा था दुलदुल जुलूस

मोहर्रम पर छोटा चौक में बैठाए सबसे बड़े दुलदुल को मोहर्रम की 10 तारीख पर मुस्लिम समाज के लोग कंधों पर उठाकर आजाद चौक में लाते हैं। कुछ देर रुकने के बाद अखाड़ों का प्रदर्शन होता है। इसके बाद यहां से दुलदुल को उठाकर मीरकलां, कसाईवाड़ा, किला रोड से होते हुए छोटा चौक के समीप स्थित इमामबाड़े में सुबह 5 बजे रखा जाता है। इस दौरान दुलदुल को उठाकर दौड़ भी लगाई जाती है। ऐसे में इस बार भी रविवार को मोहर्रम की 10 तारीख पर देर रात दुलदुल को छोटा चौक से उठाकर आजाद चौक में लाकर रखा गया।

दो युवकों के बीच हुआ विवाद

इसी दौरान दुलदुल को रखने का टेका मांगने पर दो युवकों के बीच कहासुनी और फिर गाली-गलौज होने लगी। बताया गया पुरानी बात को लेकर युवकों के साथी भी विवाद में शामिल हो गए। इससे आजाद चौक में गहमा-गहमी का माहौल बन गया। दोनों गुटों के बीच थप्पड़ों से मारपीट होने लगी। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर तैनात पुलिस तत्काल एक्शन में आई और विवाद करने वालों के साथ ही उपद्र?वियों को डंडे फटकार कर खदेड़ दिया।

मंच से बोले गए अपशब्द

मंच से अपशब्द सुनकर गर्माया माहौल-जिस समय आजाद चौक में दोनों युवक और साथियों के बीच गहमा-गहमी हो रही थी और थप्पड़ मारे गए। तभी एक गुट के व्यक्ति ने आजाद चौक में लगाए हुए मोहर्रम कमेटी के मंच पर चढ़कर माइक पर दूसरे गुट के व्यक्ति का नाम लेकर अपशब्द कहे। इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी।

प्रशासन से चर्चा के बाद होगा चालीसवें पर फैसला

आजाद चौक में मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुए इस विवाद के बाद पुलिस ने सभी उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इसके बाद सबसे बड़े दुलदुल को आजाद चौक से सीधे छोटा चौक ले जाकर इमामबाड़े में रखवा दिया। रात करीब 2 बजे दुलदुल को रखने के बाद पुलिस ने सभी को घर भेज दिया। बताया गया कि इस दौरान मोहर्रम कमेटी के जिम्मेदारों ने मंच से ही घोषणा कर दी कि चालीसवें पर निकलने वाले सबसे बड़े दुलदुल के जुलूस को निकालने का निर्णय प्रशासन से चर्चा के बाद लिया जाएगा।

किसी ने भी पुलिस को नहीं की शिकायत

पुलिस बल के साथ ही जिपं सीईओ संतोष टैगोर, एएसपी टीएस बघेल, एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार सुनील पाटिल, नायब तहसीलदार नाहिक अंजुम सहित पटवारी और अन्य मौजूद रहे। एएसपी बघेल ने बताया मोहर्रम के जुलूस में दो गुटों में अखाड़ा घूमाने को लेकर कहासुनी हो गई। पुलिस पहले से ही तैनात थी और स्थिति को पांच मिनट में पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया। अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई गई है। क्षेत्र में पूरी तरह शांति है।

मोहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा भगवा झंडा जलाया, 4 लोग गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

प्रदेश के रतलाम जिले में रविवार देर रात में मोहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र लिखा ध्वज जलाने का मामला सामने आया है। सोमवार सुबह इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी। घटना से गुस्साए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कर विरोध जताया।

सूचना पर पुलिस प्रशासन के साथ एएसपी राकेश खाखा मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। सोमवार देर शाम पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सड़कों पर उनका जुलूस निकाला। जुलूस में आरोपी लंगड़ाकर चल रहे थे। पुलिस चारों को ऐसी ही हालात में अस्पताल मेडिकल कराने ले गई।

रतलाम जिले के सैलाना में रविवार रात को मोहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र लिखे ध्वज को मुंह में पेट्रोल डालकर गुब्बारे छोड़कर कलाबाजी दिखाते हुए जलाने का प्रयास करने का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन में आक्रोश भड़क उठा। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मस्जिद चौराहे पर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।

मौके पर एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल, रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला और थाना प्रभारी सुरेश गडरिया मौजूद रहे। सर्व हिंदू समाज और अन्य धार्मिक-सामाजिक संगठनों ने घटना को जानबूझकर की गई हरकत बताया। इसे भगवा ध्वज का अपमान कहा। इसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और शांति भंग करने के मामले में चार आरोपी शहजाद पिता सलीम मेंव, भय्यू पिता मुन्ना खान पठान, अज्जू शाह पिता रमजानी शाह, बबलू शाह निवासी कब्रिस्तान रोड सैलान को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला।

वायरल वीडियो में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक युवक मुंह में पेट्रोल भरकर आग को एक बैनर की तरफ फूंकता दिख रहा है। इस भगवा बैनर पर बड़े शब्दों में हिन्दु राष्ट्र लिखा है। आग से बैनर आंशिक रूप से जल जाता है। घटना रविवार देर रात को मस्जिद चौराहे की है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा कि मोहर्रम जुलूस के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में प्रसासन के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। किसी ने भी ऐसा कर रहे युवक को नहीं रोका। उन्होंने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है।

44 लाख से अधिक का मादक पदार्थ जब्त, दो हिरासत में

माही की गूंज, रतलाम।

अवैध मादक पदार्थ की धरपकड अभियान में बुधवार को माणक चौक पुलिस ने 440 ग्राम एम. डी ड्रग्स पकडने में सफलता प्राप्त की जिसकी कीमत 44 लाख से अधिक है।

उनि अनुराग यादव के नेतृत्व में गठित टीम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति जिनमे से एक की दाढ़ी बढ़ी हुई एवं क्रीम रंग की शर्ट व काले रंग का पैंट पहना हुआ है एवं दूसरे व्यक्ति जिसकी दाढ़ी कम व बाल काले होकर महरून रंग की टी शर्ट व काले रंग का पैंट पहनी हुई है, जो दोनों व्यक्ति अमूमन करमदी गाँव के पास आते है और एम. डी ड्रग्स की सप्लाई करते है और आज भी करमदी नमकीन क्लस्टर के पास क्षेत्र में एम. डी ड्रग्स की बिक्री करने आने वाले है, जो अपने पास अवैध एम. डी ड्रग्स छुपाकर रखते है।

यदि तत्काल घेराबंदी कर पकडा जाये तो सफलता मिल सकती है। अन्यथा देरी होने पर वह दोनों व्यक्ति निकल जाएंगे। सुचना तस्दीक हेतु थाने से हमराही फोर्स के मुखबीर बताये स्थान पहुँचकर आरोपीगणो भावेश भाई रावल पिता जितेंद्र रावल उम्र 36 वर्ष निवासी हरिओम सोसायटी मोरवी जिला राजकोट गुजरात एवं अल्पेश परघरमोर पिता सुरेश परघरमोर उम्र 25 वर्ष निवासी नाहरा बस्ती नागपूर महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर आरोपीगणो से 440 ग्राम मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स किमती 44 लाख 2 हजार रुपये की तथा नगदी 3 हजार रुपये व दो मोबाईल जप्त किया जाकर आरोपीगणो के विरुद्ध थाना हाजा पर अप.क्र. 407/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है।

पूर्व में भी 6 जुलाई को थाना माणकचौक थाना प्रभारी उनि अनुराग यादव के नेतृत्व मे उनि. प्रवीण वास्कले सउनि शिवनाथसिह राठौर, आर विशाल सैन, आर मनोहरसिह, आर राजेन्द्र चौहान, आर प्रवीणसिह के द्वारा तीन आरोपीगणो को गिरफ्तार किया जाकर आरोपीगणो से अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर 3 ग्राम, अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स 11 ग्राम मय ब्रेजा कार कुल किमती 18 लाख 5 हजार 5 सौ रुपये करीबन जप्त किया गया तथा आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध क्र.405/25 धारा 8/21,22,29 एनडीपीएस एक्ट का पंजीबद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में भावेश भाई रावल पुत्र जितेंद्र रावल (36) निवासी मोरवी (गुजरात) अल्पेश परघरमोर पुत्र सुरेश परघरमोर उम्र (25) निवासी नाहरा बस्ती नागपूर (महाराष्ट्र) है। गिरफ्तार शुदा आरोपीगणो से अवैध मादक पदार्थ के सम्बंध मे पुछताछ की जा रही है।

14 जुलाई को होंगे आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित

माही की गूंज, मंदसौर।

सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन ने जिला पंचायत सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित कर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग को दिशानिर्देश प्रदान किए। आगामी 14 जुलाई को आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी/ग्रामीण, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, उपस्वास्थ्य केंद्र इन सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। जनसमुदाय को स्वास्थ्य सुविधायें उनके निवास के निकट उपलब्ध हो इस हेतु आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर ÷आयुष्मान आरोग्य शिविरों÷ का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में स्वास्थ्य से संबंधित विविध गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

सड़क पर विधायक प्रतिनिधि की लाश मिलने से सनसनी

माही की गूंज, रतलाम।

जिले के अंतर्गत आने वाले जावरा विकास खंड के ग्राम सरसी से विधायक प्रतिनिधि सरसी निवासी कन्हैयालाल धाकड़ का मंगलवार की सुबह सरसी-केरवास मार्ग पर शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड के साथ मामले की जांच शुरु की।

इधर, सामने आई जानकारी के अनुसार, विधायक प्रतिनिधि कन्हैयालाल धाकड़ बर्थ-डे पार्टी से लोट रहे थे। इसी दौरना सरसी-केरवास मार्ग पर लगे गिट्टी और मुरम के ढेर के पास संभवत सड़क दुर्घटना का शिकार हुए होंगे। संभवतः इसी के चलते उनकी मृत्यु हुई होगी। इधर, कन्हैयालाल धाकड़ ने उनकी हत्या का आरोप लगाते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। यही नहीं परिवार के साथ-साथ क्षेत्रीय लोग पुलिस चोकी के सामने धकड़ का शव रखकर प्रदर्शन करने लगे।

मामले की जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि, जांच एकदम निष्पक्ष की जा रही है। पीएम रिपोर्ट और आगामी जांच के बाद स्पष्ट होगा कि, ये महज एक सड़क हादसा है या शातिराना ढंग से की गई हत्या।

रतलाम एसपी अमित कुमार ने मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सूचना पर जावरा सीएसपी दुर्गस आर्मो ओर थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे हैं। गुस्साये ग्रामीण जनों ने सरसी गांव को बंद करा दिया है और चौकी कर बाहर प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहे है।

दो हफ्ते पहले हुआ था विवाद

विधायक प्रतिनिधि का शव मिलने से दो हफ्ते पहले गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। जिस पर धाकड़ ने एसपी अमित कुमार से न्याय की गुहार भी लगाई थी, जिसके चते पुलसि ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके बाद मंगलवार को धाकड़ का शव मिलने के बाद क्षेत्र में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल शव को पीएम के रतलाम भेजा हैं। मामले में जांच जारी हैं।

कलैक्ट्रेट भवन में फीता काटकर किया 'दीदी कैफे' का शुभारंभ

माही की गूंज, मंदसौर।

मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, ग्राम माल्याखेड़ी, विकासखंड मंदसौर की 'जय मां संतोषी स्व सहायता समूह' द्वारा संचालित 'दीदी कैफे' का भव्य शुभारंभ कलेक्टर कार्यालय मंदसौर में कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने पारंपरिक रूप से फीता काटकर, दीप प्रज्वलन, पूजन अर्चन करके किया। शुभारंभ अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, जिला परियोजना प्रबंधक एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्य अधिकारी, कर्मचारी तथा जिले भर से आई स्व-सहायता समूहों की महिलाएं (दीदियाँ) सम्मिलित हुईं।

'दीदी कैफे' का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस पहल के तहत समूह की महिलाएं कलेक्टर परिसर में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों को स्वच्छ, पौष्टिक एवं किफायती दर पे चाय, कॉफी, पोहा एवं अन्य नाश्ता सामग्री उपलब्ध कराएंगी। यह कैफे केवल एक व्यावसायिक उपक्रम नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की क्षमता, आत्मबल एवं आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक सिद्ध होगा। 'दीदी कैफे' स्वाद, स्वच्छता और सशक्तिकरण का संगम है।

एसडीएम से साइबर फ्रॉड की कोशिश

माही की गूंज, रतलाम।

पुलिस प्रशसन के तमाम प्रयासों के बावजूद सायबर ठगों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि, अब वो आमजन तो छोड़िए प्रसासनिक अफसर तक को ठगने से पहले फंसने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा विकासखंड से, जहां ठगों ने किसी और को नहीं बल्कि जावरा एसडीएम को ही ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया है। ठगों ने एसडीएम त्रिलोचन गौड़ से लड़की का शव हजारों किमी दूर पहुंचाने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रयास कर दिया। हालांकि, एसडीएम गौड़ की सूझबूझ के चलते वो ठगी का शिकार होने से बच गए।

ठगी का ये तरीका आपको हैरान कर देगा, क्योंकि जालसाजों ने एसडीएम को अपना शिकार बनाने के लिए मृत लड़की का शव कहीं दूर ले जाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया। पहले तो एसडीएम को लगा कि वास्तव में किसी जरुरतमंद को मदद की जरूरत है, लेकिन जब उन्होंने मृतक का नाम-पता, घटनास्थल आदि की जानकारी ली तो ठग सतर्क हो गया और आधे घंटे बाद शव के लिए आइस पैक के लिए 3 हजार देने की बात करने लगा। समय पर जानकारी निकलवाने और सतर्कता से ठग का ये प्रयास विफल हो गया। हालांकि ये मामला 23 जून का है। इसके बाद एसडीएम अवकाश पर चले गए थे और अब उन्होंने इसे मीडिया के सामने रखा है।

जावरा एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को बीते 23 जून को अनजान नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा कि वो जीआरपी थाना बिलासपुर से आरक्षक बात कर रहा है।

आपके क्षेत्र सरसी की एक लड़की हमारे क्षेत्र में ट्रेन दुर्घटना की शिकार होकर मौत हो गई है। इसकी मृत्यु होने पर इसकी डेड बॉडी को वहां तक भिजवाने के लिए हमें आपके यहां से सहायता की जरूरत होगी। इसे भेजने के लिए जो एम्बुलेंस भेजी जा रही है, उसमें डीजल डलवाने के लिए सहायता राशि आप वहां से किसी अधिनस्थ के जरिए भिजवा दें।

इसपर एसडीएम ने पूछा- पूरा मामला क्या है यह बताइए। साइबर फ्रॉड ने पूरा मामला बताया और कहा कि ये सरसी गांव की लड़की है। उसका नाम पूजा साहू है। ट्रेन से गिरकर उसकी मृत्यु हुई है। इसके परिवारजन सभी जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा पर गए हैं, उसके घर में कोई नहीं है। इसलिए मदद की जरूरत पड़ रही है। एसडीएम ने तहसीलदार संदीप इवने को नंबर देकर इसकी जानकारी निकालने को कहा तो उन्होंने तहसीलदार को भी वही जानकारी दी।

चौकी से पता चली सच्चाई

एसडीएम और तहसीलदार ने इसके बाद सरसी चौकी प्रभारी और पटवारी को गांव भेज कर वस्तु स्थिति की जानकारी जुटाई। लेकिन, गांव में न तो इस नाम की कोई लड़की रहा करती थी और न ही कोई परिवार। यही नहीं, इस पूरे गांव से कोई एक भी व्यक्ति जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा तक नहीं गया था। इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि, ये किसी और का नहीं, बल्कि साइबर जालसाजों का कॉल है।

दोबारा कॉल कर मांगे साढ़े तीन हजार

एसडीएम गोड़ ने बताया कुछ देर बाद फ्रॉड का दोबारा कॉल आया। उसने कहा- हमने डीजल का इंतजाम तो थाने से ही कर लिया है, आप सिर्फ साढ़े तीन हजार रुपए हमें बॉडी के ऊपर रखने के लिए बर्फ के भिजवा दें, क्योंकि 800 किलोमीटर दूर इस बॉडी को भेजना है तो इसमें बर्फ नहीं होने के कारण बदबू आने लगेगी। इसपर अधिकारियों ने उसे बताया कि, हमने सरसी गांव में पता कर लिया है। उस गांव में ना तो ऐसी कोई लड़की रहा करती थी और न ही कोई परिवार। यहां तक की पूरे गांव से कोई भी जगन्नाथ पुरी यात्रा तक में नहीं गया। ये सुनते ही सामने वाले शख्स ने कॉल कट कर दिया।

तीसरी बार कॉल कर कहां की रतलाम में रहती है

फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने अधिकारी को तीसरी बार फिरफोन किया। इस बार उसने मृतका को रतलाम निवासी बताया। जालसाज ने फोन पर कहा कि, पहले वो युवती उसी गांव में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से वो रतलाम में शिफ्ट हो गई है। इसपर अधिकारियों ने कहा- आप हमें रतलाम का पता बता दे दें, हम वहां पता करवा लेंगे इससे वह फ्रॉड करने वाला डर गया और उसने फोन काट दिया। इसके बाद अधिकारियों ने बिलासपुर जीआरपी थाने के अधिकारी से फोन पर संपर्क किया तो पता चला कि, उस नाम का वहां कोई आरक्षक तक नहीं है। फिलहाल, एसडीएम की सूझबूझ से वो खुद ठगी का शिकार होने से बच गए।

सीवरेज कार्य बना जानलेवा बैल फंसा 10 फीट गहरे चेंबर में

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी के वार्ड क्रमांक 02 स्थित राजघाट मार्ग पर बुधवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। सुबह करीब 7 बजे एक बैल लगभग 10 फीट गहरे सीवरेज लाइन के चेंबर में गिर गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव का प्रयास किया, लेकिन चेंबर की गहराई और बैल के वजन के कारण सफलता नहीं मिली। नर्मदा दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु विष्णु वनडे और अन्य लोगों ने भी मदद की। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से बैल को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ है। सीवरेज कार्य के दौरान पहले भी मिट्टी धंसने से दो वाहन और एक खुदाई करने वाली मशीन फंस चुकी है। समाजसेवी और पार्षद ठेकेदार की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज हैं। विष्णु वनडे ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हर बार हादसे होते हैं और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा रहता है।

स्थानीय नागरिकों ने बताया कि निर्माण स्थल पर न तो कोई घेराबंदी की गई है और न ही कोई चेतावनी पट्टिका लगाई गई है। सीवरेज पाइप डालने और चेंबर बनाने के बाद गड्ढों में केवल मिट्टी डाल दी जाती है। बारिश में यह मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं।

वार्ड क्रमांक 02 के पार्षद ईश्वर यादव ने कहा कि नगर परिषद और सीवरेज निर्माण करने वाली कंपनी की लापरवाही से गलियां कीचड़ से भरी पड़ी हैं। अब तक मुरम तक नहीं डाली गई है। बारिश में गड्ढे और फिसलन के कारण बाइक सवार, बच्चे, बुजुर्ग सभी परेशान हो रहे हैं।

स्थानीय निवासी रजत ने बताया कि नगर परिषद को कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बैल को लोग मरता देख रहे थे, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं आया।

राजघाट मार्ग अब सड़क नहीं बल्कि गड्ढों का जाल बन चुका है। बारिश में गड्ढे दिखाई नहीं देते और राहगीर गिरते रहते हैं। बाइक, साइकिल, पशु सभी इस अव्यवस्था के शिकार हो रहे हैं।

राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग प्रतियोगिता में चमकाया नाम, जीते तीन पदक

माही की गूंज, खंडवा।

विशाखा पाराशर ने चेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय पैरा फेंसिंग प्रतियोगिता में शानदार सफलता हासिल की है। 4 से 6 जुलाई तक चली इस प्रतियोगिता में विशाखा ने बी श्रेणी में एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीतकर जिले और मध्यप्रदेश का नाम रोशन किया।

विशाखा वर्तमान में गांधीनगर स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में नियमित प्रशिक्षण ले रही हैं। उनका अगला लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर भारत के लिए पदक जीतना है। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम और मजबूत इरादों से यह साबित कर दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, यदि संकल्प मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।

वर्ष 2015 में एक दुर्घटना के दौरान छत से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी, जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर गया था। डॉक्टरों ने सामान्य जीवन की संभावना ना के बराबर बताई थी, लेकिन विशाखा और उनके परिवार ने हार नहीं मानी। पिता विजय पाराशर और माता के निरंतर समर्थन से विशाखा ने खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया और खेलों में भविष्य बनाने का निर्णय लिया।

लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अब उनकी नजरें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का परचम लहराने पर टिकी हैं।

खाद की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूटा, दो घंटे चक्काजाम

माही की गूंज, खरगोन।

किसानों ने खाद की कमी को लेकर बुधवार को बिस्टान नाका क्षेत्र में चक्काजाम कर दिया। नाराज किसानों ने भुसावल-चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर बैठकर करीब दो घंटे तक रास्ता बंद रखा। दोपहर 12-30 बजे के आसपास टोकन होने के बावजूद यूरिया खाद न मिलने से आक्रोशित होकर 300 से अधिक आदिवासी किसान सड़क पर बैठ गए।

जिला मुख्यालय पर पिछले एक सप्ताह से यूरिया खाद की कमी बनी हुई है। किसानों को पहले टोकन लेना पड़ रहा है और फिर घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। बुधवार को खंडवा से यूरिया खाद की रेलगाड़ी नहीं आने से 200 से अधिक टोकनधारी किसान परेशान हो गए।

सूचना मिलने पर खरगोन के अनुविभागीय अधिकारी बीएस कलेश, कृषि उप संचालक शिव सिंह राजपूत, कोतवाली पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को 13 जुलाई को खाद की रेलगाड़ी आने का भरोसा दिलाया। करीब दो घंटे बाद स्थिति सामान्य हो पाई। इस वर्ष जिले में खरीफ सीजन के लिए 75 हजार मीट्रिक टन यूरिया की मांग की गई थी, जिसके मुकाबले अब तक सिर्फ 45 हजार मीट्रिक टन की आपूर्ति हुई है। खरीफ फसल का समय होने के कारण खाद की मांग अधिक है। किसानों का आरोप है कि बाजार में खाद महंगे दामों पर बेची जा रही है।

दूध उत्पादन प्रतियोगिता के विजेताओं को मिले पुरस्कार

माही की गूंज, बड़वानी।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग बड़वानी के जिला कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत बड़वानी के अध्यक्ष बलवन्तसिंह पटेल ने विजेता गौपालकों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकासखण्ड पाटी जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष ज्ञानसिंह ने की एवं विशेष अतिथि के रूप में भूपेन्द्र गोयल उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 30 प्रतिभागियों को 5-5 लीटर कैल्शियम प्रदान किया गया। गायों की दूध उत्पादन प्रतियोगिता में तलवाड़ा बुजुर्ग निवासी योगेश पिता राजेश सोनपड़ा की भारतीय उन्नत नस्ल गिर गाय ने 14.347 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं बड़वानी निवासी अपूर्व पिता राजेश जोशी की मूल गौवंशीय निमाड़ी नस्ल की गाय ने 10.223 लीटर दूध देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

भारतीय उन्नत नस्ल गिर गाय वर्ग में बड़वानी निवासी खेमालाल पिता धन्नालाल धनगर ने द्वितीय एवं राधेश्याम पिता गंगाराम धनगर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार निमाड़ी नस्ल वर्ग में जोगवाड़ा निवासी राजेश पाटीदार ने द्वितीय एवं कुआ निवासी रविन्द्र मुकाती ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

गौवंशीय दुधारू नस्लों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उप संचालक एल.एस. बघेल ने बताया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले गौपालकों को क्रमशः 51 हजार, 21 हजार एवं 11 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। इनका विवरण प्रदेश स्तर पर भी भेजा जाएगा।

क्क कार्यक्रम के पूर्व जिले के कार्यरत गौसेवक एवं मैत्री गौसेवकों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए।

क्क कार्यक्रम के अंत में जिला कार्यालय परिसर में अतिथियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस प्रतियोगिता में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी राजेश पाटीदार, सहायक नोडल अधिकारी महेन्द्र बघेल एवं सभी विकासखण्ड स्तरीय अधिकारी-कर्मचारियों का योगदान उल्लेखनीय रहा।

बिना अनुमति बनाए फर्जी प्रमाण पत्र, विदेशों में बेची जैविक कपास

माही की गूंज, खरगोन।

सेगांव क्षेत्र में जैविक खेती के नाम पर बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों ने चार कृषक समितियों पर उनके दस्तावेजों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, आधार क्रमांक और खेतों की जानकारी का उपयोग किया गया। इन दस्तावेजों से फर्जी जैविक प्रमाण पत्र और लेनदेन प्रमाण पत्र बनाए गए। इन प्रमाण पत्रों का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कपास की बिक्री के लिए किया गया। पीड़ित किसानों का दावा है कि उन्होंने कभी जैविक कपास की खेती ही नहीं की।

किसानों ने पुलिस अधीक्षक और कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। रामदास, फूलसिंह, सरदार और श्यामदास सहित कई किसानों ने रामकोला कृषक उद्यान समिति, विरई कृषक उद्यान समिति, ईको नेक्टर खेड़ापुरा और ईको नेक्टर छोटा डाबरपुरा के संचालकों के विरुद्ध शिकायत की है। उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और कृषि कार्यालय में कार्रवाई की मांग की है।

आठ दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

किसान नेता महेश पाटीदार के अनुसार जिले में 100 अधिक कृषक समितियाँ हैं, जिनमें 50 हजार से अधिक किसान प्रभावित हो सकते हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि आठ दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे।

उप संचालक कृषि शिवसिंह राजघूत ने बताया कि इस मामले में पूर्व में भी शिकायतें मिली थीं। एक समिति बनाकर मामले की जाँच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी।

ठोस रणनीति से ही हिमाचल में नशामुक्ति की राह

हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से एक सशक्त संदेश देते हुए पुलिस ने केवल एक महीने में ही 250 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ नशा तस्करी के आरोप में मुकदमें दर्ज किए हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 183 एफआईआर दर्ज की गई हैं। प्रदेश में 14 मामले वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ रखने के लिए, 85 मामले मध्यम मात्रा के लिए और 58 मामले छोटी मात्रा के लिए दर्ज किए गए। लगभग दो दर्जन मामले नशीली दवाओं की खेती से संबंधित थे। एक सकारात्मक कदम के रूप में पुलिस ने पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत 21 निवारक प्रस्तावों पर कार्रवाई शुरू की है। राज्य पुलिस ने सक्षम प्राधिकारी से आधा दर्जन आदेश प्राप्त करने में भी सफलता हासिल की है।

लगभग तीन दशकों से मादक पदार्थों की समस्या कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तस्करी ने केवल गांजा केंद्रित व्यापार से बदलकर छिपाने में आसान और उच्च कीमत वाले सिंथेटिक ड्रग्स की स्मगिंलग का रूप ले लिया है। दूरदराज व दुर्गम इलाके का फायदा उठाते हुए अपराधी यहां अफीम की अवैध खेती भी करते हैं।

वर्ष 2019 के नशीले पदार्थों के उपयोग संबंधी राष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश के लिए कोई गंभीर चेतावनी नहीं दी गयी थी। हालांकि, तब से काफी कुछ बदल चुका है। समस्या की सटीक स्थिति जानने के लिए राज्य स्तर पर एक नमूना सर्वेक्षण की तत्काल आवश्यकता है। पुलिस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में 41 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। राज्य के लिए चिंताजनक बात यह है कि मादक पदार्थों के मामलों में गिरफ्तार किए गए 90 प्रतिशत से अधिक लोग 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के हैं। राज्य की जेलों में लगभग तेरह सौ युवा मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में बंद रहते हैं। राज्य का कोई भी जिला मादक पदार्थों की समस्या से अछूता नहीं है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में इस श्रेणी के अधिकतम मामले दर्ज होते हैं।

राज्य की जेलों में एनडीपीएस मामलों से जुड़े दोषी और अभियुक्त कैदियों की संख्या अधिक है। लगभग 40 प्रतिशत पुरुष कैदी, चाहे दोषी हों या अभियुक्त, मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में शामिल हैं। महिलाओं के लिए यह आंकड़ा लगभग 30 प्रतिशत है। छोटी मात्रा के तस्कर अक्सर स्वयं भी नशीली दवाओं का इस्तेमाल करने वाले होते हैं। लगभग 10 प्रतिशत कैदियों को नशामुक्ति और पुनर्वास कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों का स्थान जेल नहीं बल्कि पुनर्वास केंद्र होना चाहिए। पुनर्वास के लिए कोई भी तय प्रोटोकॉल न होने के कारण, सुधार गृहों में तैनात चिकित्सक मादक पदार्थों के उपयोगकर्ताओं के उपचार में दक्ष हो गए हैं। राज्य के सुधार विभाग का प्रयास, जो एक केंद्रीय जेल में पुनर्वास केंद्र शुरू करने के लिए एक केंद्रीय योजना का लाभ उठाना चाहता था, राज्य सरकार के एक बाबू द्वारा खारिज कर दिया गया ! राज्य सरकार को उन सभी सुधार गृहों को, जहां समर्पित चिकित्सक तैनात हैं, औपचारिक रूप से मादक पदार्थ पुनर्वास केंद्र घोषित करना चाहिए।

राज्य की मादक पदार्थ समस्या के प्रति प्रतिक्रिया अब तक टिकाऊ नहीं रही है, जिसने संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले, राज्य सीआईडी के तहत एक एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) स्थापित की गई। बाद में, एक राज्य कानून पारित किया गया और एक विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) बनाई गई, लेकिन एएनटीएफ को समाप्त नहीं किया गया। एसटीएफ, जिसका नेतृत्व एडीजी स्तर के अधिकारी करते हैं, लगभग कमजोर है क्योंकि उसमें पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। यह एक क्लासिक मामला है, जिसमें सिलसिला बेतरतीब है। आज, ये दोनों एजेंसियां अपने कार्यक्षेत्र और अधिकारों के स्पष्ट विभाजन के लिए संघर्ष कर रही हैं।

एनडीपीएस मामलों की इंटेलिजेंस, रजिस्ट्रेशन और जांच समन्वय के लिए पुलिस रेंज स्तर पर तीन पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। यह प्रणाली अच्छी तरह काम कर रही है। इसे पारदर्शी कमांड श्रृंखला और जवाबदेही के साथ और मजबूत करने की जरूरत है। अतिरिक्त निरीक्षण के स्तर और प्रतिस्पर्धात्मक अधिकार क्षेत्र बनाने से राज्य के प्रयासों में भ्रम बढ़ेगा।

यह भी पता चला है कि राज्य ने नशा संबंधी नीति मार्गदर्शन देने के लिए सेवानिवृत्त नौकरशाहों की एक समिति बनाई है! गृह विभाग खुद संभाल रहे मुख्यमंत्री को इस समिति को भंग कर देना चाहिए और उनके वेतन से बचाए गए धन का उपयोग एक व्यापक सर्वेक्षण करने में करना चाहिए, जिससे समस्या को पूरी तरह समझा जा सके। राज्य के पास अपने मौजूदा सेवारत अधिकारियों के रूप में पर्याप्त टैलेंट मौजूद है जो इस मामले को संभाल सकते हैं।

मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना एक विशेष कार्य है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को संबोधित करना अलग बात है, लेकिन निरंतर अभियानों को बनाए रखना, मादक पदार्थ उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और उन्हें परामर्श देना अलग। पुलिस को यह कार्य बिना आवश्यक मानव संसाधन के देना सही नहीं होगा। युवाओं को परामर्श देने के लिए उचित प्रशिक्षण आवश्यक है। राज्य का सामाजिक कल्याण विभाग पुलिस के साथ मिलकर इस कार्य को सफल बनाने के लिए काम करे।

सोमेश गोयल

मादक पदार्थ उपयोगकर्ताओं के परिवार आमतौर पर अपने परिजनों की समस्या को स्वीकार नहीं करते। कोई भी परिवार मादक पदार्थ उपयोगकर्ताओं की पहचान करने, उनके परामर्श, भावनात्मक समर्थन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा एनजीओ से संपर्क कर उनका नशा छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पंचायतें जमीनी स्तर पर लोगों के साथ निकटता से काम करती हैं। उनकी सूचना किसी बाहरी एजेंसी से बेहतर होती है। इस संसाधन का उपयोग एक प्राथमिक डाटा तैयार करने और रणनीति बनाने के लिए किया जाना चाहिए।

राज्य में एनडीपीएस मामलों में वित्तीय जांच नगण्य है। राज्य पुलिस को अपने तंत्र को व्यापक बनाना चाहिए और संगठित माफियाओं का निरंतर पीछा करना चाहिए। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान केवल एक महीने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। देवभूमि हिमाचल को निरंतर इंटेलिजेंस संग्रह, निगरानी, प्रवर्तन और तेज़ अदालती कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि इस स्थिति में वास्तविक सुधार हो सके। युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और आम समुदाय में जागरूकता जरूरी है। पूरे मामले को कलंक से सहानुभूति की ओर ले जाना होगा। इस क्षेत्र के विशेषज्ञता वाले कुछ प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग भी लाभकारी हो सकता है।

इस जिले में रविवार को खुलेंगे स्कूल

माही की गूंज, उज्जैन।

11 जुलाई 2025 से पवित्र सावन मास की शुरुआत होने जा रही है। इसे लेकर पूरे देश में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं, महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रशासन ने हर सोमवार को स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि, इसे लेकर अब सियासी खेमे में बवाल मच गया है। मध्य प्रदेश प्रशासन के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं।

उज्जैन के कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने नोटिस जारी करते हुए सावन महीने के सभी सोमवार पर स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं।

सोमवार को छुट्टी, रविवार को खुलेंगे स्कूल

कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, 14 जुलाई से 11 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार को सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। उज्जैन नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों पर यह आदेश लागू होगा। हालांकि, सोमवार की जगह रविवार को स्कूल खुले रहेंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

नोटिस में लिखा है-

सावन में भगवान महाकालेश्वर की सवारी के मद्देनजर उज्जैन नगरपालिका के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिया जाता है कि 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई, 4 अगस्त और 11 अगस्त को पड़ने वाले सभी सोमवारों पर स्कूल बंद रहेंगे। इन तारीखों की बजाए 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 अगस्त, 3 अगस्त और 10 अगस्त को पड़ने वाले सभी रविवार पर स्कूल अपने तय समय के अनुसार चलेंगे।

कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

प्रशासन के इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ÷महाकाल की सवारी सालों से निकल रही है। हर समाज और वर्ग के लोग इसका समर्थन करते हैं। मगर दुर्भाग्यवश कलेक्टर ने सिर्फ मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए यह अप्रासंगिक आदेश जारी कर दिया है। उज्जैन में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो इस बार ऐसा क्या खास है जो स्कूलों में छुट्टी की जरूरत पड़ गई और रविवार को स्कूल खोलने का आदेश दे दिया गया है?÷

अन्य धर्मों के लोग भी मांग करें तोः आरिफ मसूद

आरिफ मसूद ने प्रशासन के इस आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा, ÷अगर अन्य धर्म के लोग भी अपने त्योहारों पर ऐसी मांग उठाने लगे तो क्या होगा? इसलिए देश को संविधान के अनुसार चलाना बेहतर होगा।÷

बीजेपी ने किया पलटवार

बीजेपी विधायक रामेश्वरम शर्मा ने भी आरिफ मसूद पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने का आरोप लगाया है। रामेश्वरम शर्मा ने कहा- सावन के सोमवार पर स्कूल बंद होने से सभी माता-पिता खुश होंगे कि उन्हें महाकाल के दर्शन करने और उनकी सवारी में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। मगर यह कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि न उन्हें भगवान राम का आशीर्वाद मिला, न श्री कृष्ण का और न ही महादेव का। कांग्रेस सिर्फ आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने में व्यस्त रहती है। मुझे लगता है यह कांग्रेस चीन और पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है। रही बात कलेक्टर के आदेश की, तो जनहित में उन्हें अवकाश घोषित करने का पूरा अधिकार है।

बाबा महाकाल की सवारी

बता दें कि सावन के सोमवार पर उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकालने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन बाबा महाकाल पूरे शहर के भ्रमण पर निकलते हैं। इस दौरान महाकाल की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सड़क किनारे खड़े होकर घंटों इंतजार करते हैं।

अवैध रूप से संचालित क्लीनिक पर हुई कार्रवाई

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर के निर्देशानुसार जिले में संचालित अवैध हेल्थ क्लीनिक एवं डॉक्टरों के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी तपीस पांडे के द्वारा अलग-अलग स्थानों पर अलीराजपुर के ग्राम नानपुर में छापामार कार्रवाई की गई। छापामार कार्यवाही के दौरान अपूर्व राय द्वारा माली मोहल्ले मे क्लीनिक एवं दंत चिकित्सक के रूप में क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था, जबकि संबंधित के द्वारा एलोपैथी से इलाज करने के कोई मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए, इस तरह प्रकाश मंडल द्वारा घर में ही होम नर्सिंग का संचालन किया जा रहा था इनके पास से मौके पर एलोपैथिक इलाज से संबंधित कोई मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। अनुविभागीय अधिकारी पांडे ने जानकारी दी कि बगैर किसी डिग्री के अवैध रूप से संचालित क्लीनिक को सील करने की कार्रवाई की गई। संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को संबंधित के खिलाफ प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्लिनिक में उपयोग में ली जा रही दवाइयों को जब्त किया गया। इस दौरान तहसीलदार श्रीमती सविता राठी , ग्राम नानपुर पटवारी एवं राजस्व अमला सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि, आगामी दिवसों में इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

ग्राम में कलश रथ यात्रा का किया स्वागत

ज्योति कलश रथ यात्रा जन्म शताब्दी वर्ष 2026 का संदेश दे रही है- श्री वर्मा

माही की गूंज, आम्बुआ।

शांतिकुंज हरिद्वार में प्रज्जवलित अखण्ड दीपक और परम वंदनीय माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की तैयारी व प्रचार प्रसार हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार कि ज्योति कलश रथ यात्रा का स्वागत पूजन ग्राम के प्रमुख लोगों द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2025 बुधवार को प्रातः 10:30 बजे किया गया। पश्चात यह ज्योति कलश रथयात्रा गांव के प्रमुख मार्गो से होकर राममंदिर पहुंची। रथयात्रा का संचालन वरिष्ठ परिजन श्री बद्रीलाल राठौड़ ने किया। राममंदिर पर गायत्री यज्ञ सम्पन्न किया जिसमें गांव वालों ने यज्ञ में भाग लेकर गांव कि सुख- शांति व समृद्धि के लिए आहुतियां समर्पित की।

गायत्री यज्ञ का संचालन महिला मण्डल कि श्रीमती ज्योति राठौड़ और श्रीमती दीप्ति राठौड़ ने किया यज्ञ के पश्चात यात्रा के उद्देश्य के बारे में जिला समन्वयक संतोष वर्मा ने बतलाया कि, शांतिकुंज हरिद्वार में अखण्ड दीपक प्राकट्य शताब्दी वर्ष एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी के शताब्दी वर्ष 2026 का संदेश देने के लिए ज्योति कलश रथ यात्रा देश के गांव गांव में निकली जा रही है। इस यात्रा में गायत्री मंत्र कि महत्ता के बारे में बतलाया गया और व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के लिए हर व्यक्ति को साधना से जुड़ने के लिए बतलाया क्षय गया। इस यात्रा में गायत्री शक्तिपीठ अलीराजपुर के समस्त भाई, महिला मण्डल कि बहने एवं ग्राम आम्बुआ क़स्बे के गायत्री परिवार के सदस्यों तथा समस्त हिन्दू धर्मावलंबियों एवं महिला मंडल के सदस्यों आदि का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ हवन आदि कार्यक्रम उपरांत रथ को पुनः आलीराजपुर की ओर प्रस्थान किया गया।

जिला स्तरीय पोषण समिति की मासिक बैठक का आयोजन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय पोषण समिति की मासिक बैठक का आयोजन कलेक?टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में किया गया।

बैठक के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री मोनिका बघेल द्वारा पोषण ट्रैकर एवं संपर्क ऐप पर होने वाली प्रविष्टियों एवं पोषण के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सक्षमआंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के सुचारू क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी, पोषण आहार वितरण व्यवस्था का जिला कलेक्टर के ÷की परफॉर्मेंस इंडिकेटर÷ (केपीआई) के रूप में समन्वय और मूल्यांकन, अति गंभीर एवं मध्यम कुपोषित बच्चों (एसएएम / एमएएम) की बच्चों के पोषण स्तर में सुधार पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता, मानक, ताजा गर्म पका भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु यह आवश्यक हैं कि उक्त भोजन शुद्धता से तैयार हो जिसके लिये निर्धारित किचन शेड, पर्याप्त साफ-सफाई एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस बैठक, ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी स्तरीय प्रबंधन समिति, समग्र पोषण हेतु आयुष आवधारणा को सम्मिलित करना आयुष विज्ञान के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती पाने के लिये स्वदेशी पारम्पिरिक पद्धतियों का उपयोग कर पोषण आवश्यकताओं की प्राप्ति की जा सकती है, पोषण वाटिका स्थापित करना। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं नाश्ते को रुचिकर बनाये जाने हेतु नाश्ता आरटीई के रूप में दिये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

बैठक दौरान कलेक?टर डॉ बेडेकर ने परियोजना अधिकारी उदयगढ़ एवं कट्ठीवाड़ा की कार्य प्रणाली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंगनवाड़ी ओपन, आधार ई-केव्हैसीएफआरएस, एचसीएम, एआरसी में कुपोषित बच्चों को भर्ती करने संबंधी बिन्दुओं की प्रविष्टि के आधार पर सीएनएस जारी करने के निर्देश दिये गए।

बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रखर सिंह, अनुविभागीय अधिकारी तपीस पांडे, जिला वानिकी अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे।

डीएलसीसी की बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, धार। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के तहत पंचायत स्तर पर चलाए जाने वाले विशेष पंजीयन अभियान को लेकर जिला स्तरीय बैंकर्स समीक्षा एवं सलाहकार समिति की विशेष बैठक कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। आयोजित बैठक में सीईओ अभिषेक चौधरी और जिले के बैंकर्स उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने अभियान को गंभीरता से संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि हर बैंक यह स्पष्ट करे कि उन्हें कहाँ-कहाँ शिविर लगाने की आवश्यकता है। यह पूरी स्पष्टता होनी चाहिए कि शिविर किस स्थान पर आयोजित होंगे, वहाँ कौन अधिकारी या कर्मचारी बैठेंगे और वे कितने समय तक वहाँ उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह केवल लक्ष्य पूर्ति का मामला नहीं है, बल्कि ज़रूरतमंद हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिक उद्देश्य है। कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक पुराने खातों में री-केव्हाईसी की प्रक्रिया प्राथमिकता से की जाए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पात्र हितग्राहियों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए। अटल पेंशन योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के प्रयास हों। स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के खातों में बीमा योजना का पंजीयन किया जाए। जनधन खातों एवं बचत खातों में नामांकन की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। साथ ही बीमा योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस अभियान की दैनिक रिपोर्टिंग की जाए और प्रत्येक स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग किए जाने की बात कही गई।बैठक में सभी प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधियों, अग्रणी जिला प्रबंधक, बीमा एजेंसियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में अभियान की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि मिशन 2047 दृ सभी के लिए बीमा÷ के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा जनसामान्य को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं उचित दर पर बीमा सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बीमा समिति का गठन किया गया है।समिति के माध्यम से राज्य के नागरिकों को बीमा सेवाओं और उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाएगा। दुर्घटना अथवा मृत्यु उपरांत बीमा दावों की स्वीकृति के लिए बीमित व्यक्ति एवं उनके परिजनों को शिक्षित किया जाएगा और बीमा सुरक्षा हेतु उपयुक्त उत्पादों की योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जीवन एवं सामान्य बीमा के क्षेत्र में अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदेश स्तर पर अग्रणी बीमा कंपनियों की नियुक्ति की गई है। राज्य शासन एवं अन्य बीमा कंपनियों के सहयोग से राज्य बीमा योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

एक पेड मॉ के नाम हेतु किया पौधरोपण

माही की गूंज, धार। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर द्वारा बुधवार को विकासखण्ड तिरला के आदर्श ग्राम सलकनपुर में आयोजित एक पेड मॉ के नाम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में नागेश्वर मंदिर के दर्शन एवं गाय पूजन करके शमशान घाट पर त्रिवेणी का रोपण किया गया। साथ ही बालाजी परिसर, शमशान घाट एवं नागेश्वर मंदिर के लिए नवांकुर समिति परम वैभव सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा बावडी की सुंदरता हेतु स्वच्छता कार्य, स्थान पर कुर्सीयॉ, विभिन्न सामाजिक व्यक्तियों द्वारा जालियों में रोपित पौधे एवं नवीन बनाये गये दर्शनीय स्थान का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम का शरीर शहर जैसा हो, किन्तु उसमें आत्मा ग्राम की होना आवश्यक है ऐसे आदर्श ग्राम का विकास आज की युवा को करना है। उसके पश्चात बालाजी धाम में हनुमानजी की पूजा करने के उपरांत बावडी, एवं स्थान का अवलोकन किया गया। जिसमें पोस्टर के माध्यम से पूर्व के स्थान एवं वर्तमान स्थान को दिखाया गया। परिसर में किए गए कार्यों का अवलोकन, बावड़ी पुनर्जीवन एवं वृक्षारोपण का अवलोकन कर मार्गदर्शन दिया गया।

आठ माह से नहीं मिला नगर निगम वाहन चालकों को भुगतान

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकाल का नगर तो है ही, इन दिनों मध्यप्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भी गृहनगर है, लेकिन इन दिनों यहां के नगरपालिक निगम के बहुत बुरे हाल हैं।

कई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने के कारण से उनका परिवार भयंकर आर्थीक संकट का सामना कर रहा है। दरअसल, बुधवार को सामने आया कि यहां नपानि के अधिकारी समेत अन्य वाहन चलाने वाले चालकों को नगर निगम से बीते आठ माह से वेतन का भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर वाहन चालक कलेक्टर के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लि. उज्जैन के वाहन चालकों ने हिस को सामूहिक रूप से बताया कि न.पा.नि. उज्जैन के अधीनस्थ चालक, परिचालक के पद पर पदस्थ होकर अपनी सेवाएँ प्रदान करते आ रहे हैं। ये सभी वर्ष 2015 से निगम के अधीन कार्य करते आ रहे हैं। निगम द्वारा निगम के अनेक उप विभागों में अधीनस्थ कर रखा है तथा विभिन्न उप विभागों में अपनी सेवाऐं आज तक निष्ठापूर्वक प्रदान करते आ रहे हैं। वहीं विगत 8 माह से वेतन प्रदान न होने से मूलभूत अधिकारों का हनन हुआ है। जिससे चालकों के बच्चों का स्कूल में एडमिशन तक नहीं हो सकें हैं।

इन्होंने बताया कि हम सभी वाहन चालकों में से कई ऐसे भी हैं, जिनके घरों में भूखमरी छा गई है, अनेकानेक विपत्तियों के बीच उधार लेकर जीवन यापन करने को मजबूर हैं, यानि हमारी सेवाएँ विभाग द्वारा ली जा रही है, मगर हमें विभाग की ओर से वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिसको लेकर हम जनसुनवाई में कलेक्टर के समक्ष भी अपनी बात रख चुके हैं और उन्हें अपनी गुहार सुनाई है। वहीं पूर्व में भी कई विभागों में हम ज्ञापन सौंप चुके हैं जिसमें अब तक न कोई कार्रवाई हुई न कोई कार्यवाही हुई है। हम सभी की यही मांग है कि काम के बदले जो वेतन हमारा बनता है, वह हम सभी को समय पर दे दिया जाए। अभी तुरंत शासन की ओर से हमारा बीते आठ माह का भुगतान अतिशीघ्र हो।

पुलिस ने नही लिखी रिपोर्ट, पीड़ित ने उतार दिए अपने कपड़े

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। इस वीडियो में एक व्यक्ति सड़क के बीचो-बीच लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आसपास से गुजर रहे वाहन हॉर्न बजा रहे, हैं लेकिन वह सड़क से हटने की बजाय कभी ट्रक तो कभी स्कूल बस के सामने लेटकर प्रदर्शन कर रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम विजय सिंह सोलंकी है।

विजय सिंह सोलंकी इंदौर का रहने वाला है। विजय का उज्जैन में ससुराल है। साल 2009 में उसकी बेटी का जन्म चरक अस्पताल में हुआ था। बेटी का जन्म प्रमाण पत्र तो है, लेकिन इस प्रमाण पत्र पर उसका नाम नहीं होने के कारण स्कूल में काफी परेशानी आ रही है। जन्म प्रमाण पत्र में बेटी का नाम दर्ज हो जाए इसीलिए विजय सिंह पिछले काफी दिनों से उज्जैन नगर निगम और चरक अस्पताल के चक्कर लगा रहा था।

प्रमाण पत्र में बेटी का नाम दर्ज नहीं होने से हुआ परेशान

काफी मशक्कत करने के बाद भी जन्म प्रमाण पत्र में बेटी का नाम दर्ज नहीं हुआ तो वह परेशान होकर ई रिक्शा से घर लौट रहा था, तभी अचानक ई-रिक्शा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया। मोबाइल चोरी होने पर विजय सिंह इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चिमनगंज थाना पहुंचा, जहां उसने पुलिस से चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्ट दर्ज करने को कहा। इस पर पुलिस ने कुछ आनाकानी कर दी।

थाने के पास ही कपड़े उतारे

इससे नाराज होकर विजय सिंह ने थाने के पास ही कपड़े उतारे और एमआर 4 रोड पर ट्रक और बस के बीच लेट गया। उसके द्वारा कपड़े उतार कर सड़क पर लेटने का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में विजय सिंह को बस और ट्रक के सामने लेटे और हाथ जोड़कर कार्रवाई करने की बात कहते हुए सुना जा सकता है।

पुलिस नहीं पहुंची लोगों ने हटाया

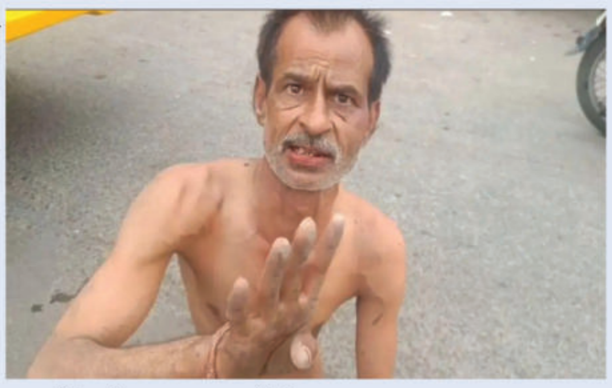

यह पूरा घटनाक्रम चिमनगंज थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही हुआ, लेकिन विजय सिंह को हटाने के लिए पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। क्षेत्र के लोगों ने ही उसको हटाया और गाड़ियों का आवागमन शुरू करवाया। यह पूरा हंगामा लगभग आधे घंटे तक चला, जिसमें पहले विजय सिंह ने कपड़े पहनकर ही हंगामा मचाया।

जब उसकी बात किसी ने नहीं सुनी तो उसने कपड़े उतार दिए और फिर गाड़ियों के आगे जाकर उन्हें रोकने लगा। इस दौरान रोड से निकल रहे लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ी

जिले के जनप्रतिनिधि नपुंशक्ता के चलते जिले के आला अधिकारियों के सामने नतमस्तक

कलम के सिपाही पहले भी कभी हारे नहीं है, और ना आगे हारेंगे

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश का यह पश्चिमी छोर पर बसा आदिवासी बाहुल जिला आजादी के बाद से अब लगातार सफर के बावजूद विकासशील जिलों की गिनती में नहीं पहुंच पाया है। आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी प्रदेश में यह जिला अतिगरीबी के मामले में अब भी दूसरे स्थान पर बना हुआ है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि, पिछले सात दशकों में यह जिला शुन्य से उठकर सिर्फ दो कदम ही चल पाया है। हालात अब भी जस के तस ही नजर आते है। विकास के नाम पर इस जिले को पिछले सात दशकों से सिर्फ और सिर्फ ठगा ही गया है। चाहे सरकारें किसी भी सत्ता दल की रही हो। जिले की इस स्थिति का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए इसके बारे में तो नही कहा जा सकता लेकिन जिले की राजनीति और नेताओं के तेवर यह बताते है कि, अगर सच्ची इच्छा शक्ति होती तो जिले को इस तरह से गरीबी का दंश नहीं झेलना पड़ता। इसमें दूसरा सबसे बड़ा हाथ अफसर शाही का है। दिक्कत यह है कि, जिले में आने वाले अधिकारी इस जिले को हमेशा से ही प्रयोग शाला बनाकर काम करते आए है। जिले में आने वाला हर अधिकारी अपनी तरह से नये-नये कामों और योजनाओं को अंजाम देता रहा है। मगर विडम्बना यह कि, इस तरह के काम और योजनाएं इस जिले में सिर्फ प्रयोग ही साबित हुए है। कभी भी कोई योजना स्थाई रूप से अब तक जमीन पर नहीं टिक पाई है। दूसरा यह कि, यहां अफसर शाही ने भ्रष्टाचार का ऐसा अंधा कुंआ खोद दिया है कि, जिले में चारों ओर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है।

वैसे तो इस जिले ने कई कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को सराहा है, तो कई निठल्ले और भ्रष्ट अधिकारियों की भर्त्सना और आलोचना की है। ऐसे अधिकारियों में कई कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी शामिल रहे है। कईयों के भ्रष्टाचार अखबारों से उजागर हुए तो कईयों को भ्रष्टाचार और निठल्ले पन की वजह से जिले से रवानगी लेनी पड़ी है। कई भ्रष्ट कलेक्टरों को न्यायालय ने दोषी ठहराया और सजा भी सुनाई। पिछले दौर में जब किसी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ किसी अखबार में कोई समाचार छपता था तब स्थिति यह बनती थी कि, या तो अधिकारी त्रुटियों में सुधार करते थे या फिर छपे समाचारों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया से बचते दिखाई देते थे। मगर अब वर्तमान में स्थितियां इससे पूर्णतः विपरीत दिखाई पड़ती है। अधिकारी अब रौब झाड़ने, डराने, धमकाने से बिल्कुल भी बाज नही आते। चाहे फिर उनके सामने कोई पत्रकार हो, आईटीआई कार्यकर्ताओं या आमजन। अधिकारियों की भाषा ऐसी कि गुंडे भी शरमा जाए। आम व्यक्ति के प्रति व्यवहार ऐसा कि, अधिकारियों के सामने फरियादी की जुबान ही सिल जाए। अधिकारियों का रौब और धौंस ऐसी कि फरियादी अपनी फरियाद तो बताता लेकिन अधिकारी उसके मुंह में अपनी जुबान डाल देते और वही लिखवाते या करवाते जो फरियादी के पक्ष में ना होकर अधिकारियों की ढाल हो या पक्ष में हो। आमजन के प्रति अधिकारियों के इस तरह के रवैये से यहां की राजनीति और नेता भी अवगत है, लेकिन नेताओं की नपुंशक्ता के चलते आमजन को अधिकारियों के कोपभांजन का शिकार होना पड़ता है। इसे इस जिले का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा।

वर्तमान में जिले की राजनीति में सत्तापक्ष का बोलबाला है, जिले में मंत्री, सांसद से लेकर विधायक तक सत्ताधारी दल के ही है। मगर स्थितियां यह बताती है कि यह सिर्फ और सिर्फ कठपुतलियां ही है। हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे बेलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के होते है। वह यह समझता है कि, बेलगाड़ी का पूरा बोझ उसी ने उठा रखा है। मगर हकीकत इसके विपरीत है। जिले में अधिकारियों और अफसर शाही का तो एक अलग ही दबदबा और दादागिरी है। स्थितियां इतनी गंभीर है कि अगर कोई जिला प्रशासन या उसके उच्च अधिकारियों के खिलाफ गया तो फिर समझो वो पूरी तरह से काम से गया। प्रशासन के खिलाफ जाने वालों के पीछे मुखबिर छोड़ दिए जाते, उनकी बेबुनियाद कमजोरियों को टटोला जाता, उनके ईशुस ढूंढे जाते और कईयों के खिलाफ फर्जी और झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती तो कई पर गंभीर मामले डाल दिए जाते। इस तरह उनकी आवाज को दबा दिया जाता। प्रशासनिक तंत्र में चल रहे इस खेल को जिले के जनप्रतिनिधि मुंक बधिर होकर देखते और सुनते रहते। मगर हिमाकत नही करते अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने की। कुल मिलाकर जिले के जनप्रतिनिधि नपुंशक्ता के चलते जिले के आला अधिकारियों के सामने नतमस्तक है। चाहे फिर वह मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या फिर किसी पार्टी का जिलाध्यक्ष, इमनें सब शामिल है। सब के सब प्रशासनिक धांधलियों, भ्रष्टाचार और अधिकारियों के रौब के आगे मुकबधिर ही साबित हुए है।

इसके विपरीत जिले की मीडिया का एक धड़ा सच्चाई और कलम की ताकत के साथ प्रशासन की बखियां उधेड़ रहा है तो दूसरा धड़ा प्रशासनिक अधिकारियों की चाटुकारिता और गोदी मीडिया का किरदार अदा करता नजर आ रहा है। चाटूकारिता भी उस स्तर की कि, समय आने पर अधिकारियों के पैर धोकर पी ले। जब कुछ निडर और निर्भिक पत्रकारों द्वारा अखबारों में जिला प्रशासन और उसमें बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की बखियां तथ्यों के साथ उधेड़ी जाती और कई संदिग्ध मामले प्रशासन के खिलाफ सुर्खियां बनते तब प्रशासन में बैठे उच्च जिला अधिकारी अपने चटगुल्ले पत्रकारों को सक्रिय करते और अपने खिलाफ छपि खबर का क्षति नियंत्रण (डेमेज कंट्रोल) करने चाटुकारों को लगा देते। ताकि नकारात्मक और सच्ची खबरों को दबाया जा सके। इस सारे खेल में चाटूकार पत्रकारिता अपना ऐसा किरदार निभाती कि, कोई पालतू कुत्ता भी शर्म से डूब मरे। यह एक नया तरीका है जो वर्तमान में जिले में बैठे आला अधिकारियों ने अपना रखा है।

हालांकि प्रशासन में बैठे आला अधिकारियों का यह स्वांग सिर्फ और सिर्फ एक कुटरचित प्रयास ही माना जाएगा जो सच्चाई को दबा नहीं सकता, भ्रष्टाचार को छुपा नहीं सकता या अखबारों में उनके उड़ते माखौल को सुर्खियों में नहीं बदल सकता। कलम के सिपाही पहले भी कभी हारे नहीं है, और ना ही आने वाले समय में हारेंगे। वे और भी ज्यादा मुखर होंगे और प्रशासनिक, राजनीतिक गलतियों, भ्रष्टाचारों को उजागर करते रहेंगे। प्रशासन की नाकामियों को आमजन के सामने रखेंगे, जनप्रतिनिधियों की नपुंशक्ता को उजागर करते रहेंगे। फिर चाहे इसकी किमत प्रशासनिक अधिकारियों की धमकियां हो, एफआईआर हो, न्यायायिक प्रक्रिया में उलझाने का जाल हो या फिर कुछ और। वैसे भी पत्रकारिता कोई गुलामी नहीं, यह हर उस बेबस, लाचार, और परेशान आम नागरिक की आजाद आवाज है जो वर्तमान में प्रशासन के भ्रष्टाचार, तानाशाही, अफसरशाही का दंष झेल रहे है। जो पत्रकारिता गुलाम है वह पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटूकारिता है। जो सिर्फ अधिकारियों के चरण चुम्बन, धोक देने तक ही सीमित है। आमजन के मुद्दे उनके लिए कोई सरोकार नहीं रखते।

पत्रकारिता जगत में पत्रकारों पर दर्ज होने वाले मामलों की एक लंबी कहानी है और यह बात कोई नई भी नहीं है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से अफसरशाही, पत्रकारिता को द्वेषता पूर्ण तरीके से टारगेट कर रही है वह यह दर्शाता है कि प्रशासनिक तंत्र में अब कुछ बचा नहीं है और बांस पूरी तरह से पोला हो चुका है। अधिकारी अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को येन-केन प्रकारेण दबाने के भरसक प्रयास कर रहे है। जिले का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि, अंत्योदय अंतिम आदमी तक विकास को पहुंचाना अब सिर्फ दीवा स्वप्न ही साबित हो रहा है।

अवैध धर्मांतरण का मामला: दो के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

माही की गूंज, खवासा।

थांदला थाना क्षेत्र की खवासा चौकी अंतर्गत पाटड़ी ग्रांम में सोमवार को अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि, गांव के ही दो व्यक्तियों ने प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। मामले की जानकारी मिलते ही हिन्दू संगठनों में आक्रोश फैल गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिलीप पिता बहादुर मेड़ा निवासी पाटड़ी ने खवासा पुलिस चौकी पर लिखित आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि, गांव के रावजी पिता कानजी डामर और कानजी पिता हुरजी डामर ने उसे फोन कर अपने घर बुलाया और पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। दिलीप ने अपने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि, आरोपितों ने पूरे गांव का धर्म परिवर्तन कराने की बात कही। जब दिलीप ने मना किया तो उसे आर्थिक लाभ देने की पेशकश की गई । दिलीप ने यह बात गांव के उदेसिंह पिता कालू मैड़ा को बताई जिस पर आरोपियों ने उदेसिंह को भी प्रलोभन देकर दिलीप के पक्ष में न बोलने की बात कही।

घटना की जानकारी मिलते ही खवासा क्षेत्र के हिन्दू संगठनों में आक्रोश फैल गया। संगठनों ने पुलिस प्रशासन से मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

खवासा चौकी प्रभारी एडमिरल तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि, दिलीप द्वारा पुलिस को दो आरोपितों के खिलाफ अवैध धर्मांतरण करवाने व प्रलोभन देने की शिकायत सोमवार को की गई थी। मामले में शिकायत सही पाई गई। मामले में दोनो आरोपियो के विरूद्ध जबरन धर्मांतरण करवाने का मामला दर्ज कर मंगलवार को आरोपियो को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

आखिर कहा है कनक? 8 दिन से लापता कनक का कोई अता-पता नही परिवार परेशान

माही की गूंज, बामनिया/अमरगढ़।

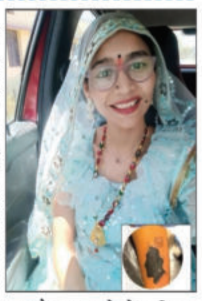

चौकी बामनिया क्षेत्र के ग्राम अमरगढ़ निवासी कनक पति चेतन पाटीदार 02 जुलाई से घर से गायब है जिसका 08 दिन बाद भी कोई अता पता नही चला जिससे महिला के परिजन पीहर ओर सुसराल पक्ष दोनों ही परेशान हैं । मामले में महिला की गुमशुदगी चौकी बामनिया में महिला के पति चेतन पाटीदार द्वारा करवाई जा चुकी हैं । परिवार सहित पुलिस महिला की खोजबीन में जुटी है । मिली जानकारी के अनुसार महिला कनक पाटीदार शादी शुदा है और अपने पति और 06 वर्षीय बच्चे के साथ अमरगढ़ में रहती हैं। 2 जुलाई को अचानक कनक घर से बिना बताए चली गई और महिला की खोजबीन आसपास और रिश्तेदारों में की गई लेकिन कोई पता नही लगा। कनक के पति चेतन ने गुमशुदगी का मामला चौकी बामनिया में दर्ज करवाया ओर कनक की फ़ोटो,पहचान सहित गुमशुदगी की रिपोर्ट शोशल मीडिया पर पोस्ट कर कनक की गुमशुदगी होने और किसी को दिखाई देने पर परिवार और पुलिस से संपर्क करने का निवेदन किया। गुमशुदगी की पोस्ट के बाद कनक पाटीदार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिंसमे कनक ने खुद को सुसराल पक्ष से प्रताड़ित होने और पीहर पक्ष से भी किसी प्रकार की सुनवाई नही होने के कारण कही भी चले जाने की बात कही। इस दौरान कनक पूरे समय रोती दिखाई दी। वीडियो सामने आने के बाद महिला की सुरक्षा को लेकर परिवार ज्यादा चिंतित हो गया। उधर पुलिस भी लगातार कनक की खोजबीन में जुटी है।

चौकी प्रभारी संजय बघेल ने बताया कि, महिला की खोजबीन जारी है और सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे लेकिन अभी कोई खास जानकारी नही मिल पाई हैं । ग्राम अमरगढ़ ओर आसपास के क्षेत्र में मामले को लेकर चर्चा का बाजार गर्म होता जा रहा है कोई परिवार पर कोई महिला पर सवाल कर रहा है । बताया जा रहा है कि कनक अपने साथ मोबाइल भी लेकर गई है लेकिन उसके जाने के बाद से उसका नम्बर बंद आ रहा है । कनक का 06 वर्षीय एक लड़का भी है जिसे वो साथ नही ले गई । आखिर कहा गई कनक ये सवाल अब हर किसी के जहन में घूम रहा है।

भटनागर की भाटगिरी सिर्फ चली एमडीएच स्कूल में...!

बामनिया के बच्चों को नहीं मिल रही एनसीईआरटी की बुक तो भामल के विद्यार्थियों को बिना कॉपीयो के नहीं मिलती किताबें

स्कूल के बच्चौ की किताबो में एमडीएच जेसी संस्था कमिशनखोरी का खेल, खेल रही है और शिक्षा के मंदिर को कंलकित कर रहै है जो चिंतनिय है।

माही की गूंज, पेटलावद/थांदला।

कहने को तो निजी स्कूलों पर शिक्षा विभाग का नियंत्रण है लेकिन यह नियंत्रण नहीं बल्कि महज निजी साठ-गांठ का ही खेल है। प्रदेश में जहां शासकीय स्कूलों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात सुर्खियों में है तो वहीं निजी स्कूलों की मान्यता में भी अनियमिताओं के साथ बीआरसी का अवलोकन व डीपीसी का फर्जीवाड़ा सामने आ ही रहा है। वही दो वर्ष पूर्व प्रदेश के जबलपुर जिले के कलेक्टर ने 80 से 90 प्रतिशत कमीशन वाली किताबें एमआरपी से बच्चों व पेरेंट्स को दिए जाने का मामला बड़ा ही सुर्खियों में रहा है। जिसमें बुक्स एजेंट व बुक्स पब्लिशर की निजी स्कूलों से साठ -गांठ के चलते कई निजी स्कूल अपनी स्कूल से ही किताबें, स्टेशनरी, जूते-मौजे के साथ यूनिफॉर्म तक बेच रहे हैं। लेकिन जबलपुर में गरमाय मामले के बाद प्रदेश भर में उसका असर दिखाई तो दिया। लेकिन कहते हैं भ्रष्टाचारियों को अगर भ्रष्टाचार करना हो तो कई तरह के रास्ते निकाल लिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही बुक्स एजेंट, बुक्स पब्लिशियर व निजी स्कूलों की साठ- गांठ के चलते ऐसा यू टर्न लिया कि, बुक्स पब्लिशियर व एजेंट द्वारा निजी स्कूलों को प्राइवेट किताबों पर सीधा कमीशन पहुंचाया जाता है। और जो किताबें एमआरपी रेट से उदाहरण के रूप में जो 100 रुपये की किताब 40 से 50 रुपये में स्थानीय बुक्स सेलर को मिलना चाहिए वह 85 से 90 रुपए में दी जाती है। बाकी का कमीशन सीधा स्कूलों को बुक्स एजेंट व बुक्स पब्लिशियर द्वारा दिया जाता है।

उक्त कृत्य का खुलासा माही की गूंज ने पूर्व में भी किया था। जिसमें इंदौर का एक बुक्स एजेंट भटनागर ने जिसने खवासा के एक स्थानीय बुक्स सेलर को स्पष्ट रूप से कहा था कि, निजी स्कूलों को हम सीधा कमीशन देते हैं। वही एमडीएच स्कूल की कुल देश में 35 स्कूल है जिसकी सभी स्कूलों की किताबें भटनागर द्वारा ही पहुंचाई जाती है तथा जिसका कमिशन दिल्ली में बैठे किसी खट्टर को सीधा कमीशन दिया जाता है। इसलिए भटनागर व भटनागर जैसे अन्य बुक्स एजेंट व पब्लिशर स्थानीय बुक्स सेलर को 10 से 15 प्रतिशत कमिशन अधिकतम दिया जाता है। इतना ही नहीं भटनागर जैसे का यह कहना है कि 10 से 15 प्रतिशत कमीशन भी बहुत है बिना कमीशन के भी स्थानीय बुक्स सेलर को बुक्स दी जाती है और वे बुक्स सेलर अपने स्टेशनरी के एवेज में बिना कमीशन वाली किताबें बेचते हैं और वो कमिशन निजी स्कूलों के संचालकों को दिया जाता है। निजी स्कूल व बुक्स पब्लिशियर तथ बुक्स एंजेंट की यह साठ-गाठ ही स्थानिय बुक्स सेलर व पेरेटंस के बिच छुट नही मिलने पर कई विवाद का कारण बनता है।

इस सत्र की बात करें तो भटनागर की कमीशन रूपी भाटगिरी सिर्फ एमडीएच स्कूल में ही खवासा व बामनिया क्षेत्र में चली है। यानीकि भामल के एमडीएच स्कूल और बामनिया की एमडीएच स्कूल में भटनागर की किताबें सप्लाई हुई है। बाकी अन्य स्कूलों ने भटनागर को बाय-बाय कह दिया है। 27 मार्च 2025 को माही की गूंज के अंक में ''कमीशन का खेल भ्रष्टाचार की रेलमपेल... कैसे स्कूल चले हम...? शीर्षक के साथ प्रकाशित समाचार के बाद कई निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग से नोटिस मिले थे।

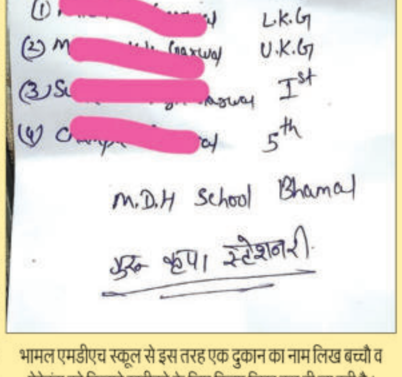

भामल एमडीएच स्कूल से इस तरह एक दुकान का नाम लिख बच्चौ व पेरेटंस को किताबे खरीदने के लिए स्लिप लिख कर दी जा रही है।

भटनागर भी बौखलाया था

वही सुनने में आया है कि, निजी स्कूलों से साठ-गांठ की बात करने वाला भटनागर के पास भी नोटिस पहुंचा था, तथा इंदौर के कुछ बुक्स सेलरों को जाकर उनके सामने अपनी बोखलाहट भी जाहिर की थी। वही एक बुक्स सेलर से भोपाल स्तरीय किसी एक अधिकारी के नंबर लेकर बात कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया था यह बताया जा रहा है। लेकिन 27 मार्च के समाचार के बाद इंदौर के अन्य बुक्स सेलर से मिली जानकारी अनुसार यह भी सामने आया कि, भटनागर बड़ा ही 4 सौ 20 है...! बताया जा रहा है कि, पूर्व वर्ष में उक्त भटनागर ने एनसीईआरटी की किताबों की बिक्री हेतु डिपो एजेंट बना था और डिपो से ली गई किताबें के साथ 4 सौ 20 भटनागर...! ने एनसीईआरटी की किताबें अन्य प्रेस में छपवाकर मोटी कमाई के साथ घिनौना कृत्य किया था। कहीं न कहीं इसकी जानकारी संबंधित विभाग एवं डिपो से संबंधित विभाग के अधिकारियों तक भी पहुंची थी और भटनागर के प्रतिष्ठान व गोदामो पर अधिकारियों ने दबिश भी दी थी यह जानकारी इंदौर के स्थानीय बुक्स सेलर द्वारा बताई गई। जानकारी में यह भी बताया गया कि, भटनागर ने उक्त मामले को हर संभव दबाने के प्रयास किये और वह सफल भी रहा।

भटनागर द्वारा दी जाने वाले किताबें व बच्चों को होने वाली परेशानी!

पिछले वर्ष तक भामल एमडीएच स्कूल में ही यूनिफॉर्म व जूते- मोजे बेचे जाने की जानकारी है। लेकिन माही की गूंज में समाचार प्रकाशित होने के बाद इस वर्ष स्कूल में यूनिफार्म बेचना बंद कर दी गई है यह बताया जा रहा है। वहीं दूसरी और बुक्स एजेंट भटनागर व स्कूल की साठ-गांठ के चलते क्षेत्र के मुख्य बुक्स सेलर ने उक्त स्कूल की किताबें रखने से मना कर दिया। नतीजा यह रहा कि, स्कूल ने भामल के एक स्थानीय व्यक्ति को गिनती की प्राइवेट किताबों का सेट दिया तो वही खवासा का एक होटल संचालक को किताबें दी गई। पर स्लिप पर प्राचार्य द्वारा खवासा की एक दुकान का नाम लिख बच्चौ को दिए जाने पर भामल के उस बुक्स सेलर ने अपनी आपत्ती जता रहा है। वही एक परेशानी यहां यह भी सामने आ रही है कि, सर्वप्रथम प्राइवेट किताबों पर कोई कमिशन एक रुपये का भी पेरेंट्स को नही दिया गया।

वही दूसरी और कोई पेरेंट्स या बच्चे अन्य स्टेशनरी दुकान से कॉपिया या रजिस्टर ले रहे हैं और वो किताबें लेने हेतु इन बुक्स सेलर के पास जा रहे हैं तो वह कह रहे हैं कि, बिना कॉपी, रजिस्टर के हम प्राइवेट बुक्स नहीं देंगे। यानीकी कॉपियों के साथ ही प्राइवेट बुक्स देने को बाध्य कर रहे हैं जिसके चलते पेरेटंस नाराज भी हो रहे है।

वहीं दूसरी ओर भटनागर व एमडीएच स्कूल की साठ-गांठ के चलते बामनिया में कोई स्थानीय स्थाई रूप से एमडीएच स्कूल की किताबें नहीं रख रहा है। एक दो वर्ष में बुक्स सेलर बदलते देखे जा रहे हैं। इस वर्ष यहां भी स्कूल की रिक्वेस्ट पर मुख्य स्टेशनरी व्यवसाय व बुक्स सेलर ने किताबें बेचने के लिए हॉं तो कर ली लेकिन वहीं प्राइवेट किताबें जो भटनागर के साथ साठ-गांठ की भेंट चढ़ स्कूल की ओर से प्राइवेट किताबें आई है वही दि जा रही है। बाकी जिन कक्षाओं में प्राइवेट किताबों के साथ एनसीईआरटी या एमपी बोर्ड की किताबें संलग्न है वह किताबें स्थानीय बुक्स सेलर नहीं दे पा रहा है। क्योंकि यह शासकीय प्रिंट की किताबें वापसी नहीं होती है और सिलेबर्स चेंज होने के कारण बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी नुकसानी से बचने के लिए शासकीय प्रिंट की किताबें नहीं मिल पा रही है। इसके चलते बच्चे परेशान होकर पेटलावद, थांदला, खवासा व रतलाम तक किताबे के लिए जाकर परेशान हो रहे हैं। वहीं भटनागर व एमडीएच स्कूल की साठ-गांठ व रिश्वतखोरी के इस खेल में महर्षि दयानंद आर्य विद्या निकेतन के संस्थापक श्री धर्मपाल जी के सेवा के वास्तविक मन्तव्य को भी कलंकित करने का यह कृत्य चिंतनीय है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422